हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 मार्च, 1978

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विषय सूचि

शुक्रवार, 3 मार्च, 1978

पृष्ठसंख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(5) 1

तारांकित प्रश्नं संख्या 228 पर आधे घण्टे की

बहस की मांग.

(5) 21

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(5) 21

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (5)

33

ध्यानाकर्षण सूचना तथा–सिंचाई एवं बिजली मन्त्री

द्वारा वक्तव्य (5)

40

राज्यपाल का सन्देश

(5) 41

विधायकों के लिये अभिविन्यास प्रशिक्षण कोर्स

सम्बन्धी अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

(5) 41

वर्ष 1978– 79 के लिए बजट पेश करना

(5) 41–67

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 3 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 9–30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Lecturers in Government Colleges

***196. Master Jogi Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of lecturers appointed by the Government in Government Colleges during the current financial year in the State;

(b) the total number of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes appeared for interview; and

(c) the total number of candidates belonging to Scheduled Castes out of those referred to in part (b) above appointed ?

श्री अध्यक्ष : साहिबान अब सवाल होंगे ।

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह :):

(ए) 89

(बी) 1 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित

(सी) 1

मास्टर जोगी राम : अध्यक्ष महोदय, 89 पोस्टस के पीछे लगभग 17 पोस्टस रिजर्वेशन की बनती हैं । क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इनको पूरा करने की कृपा की जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : : इसमे कष्ट की कोई बात नहीं है । एक ने ऐप्लाई किया था, वह ले 'लिया गया ।

मास्टर जोगी राम : मेरे पास इस बात का सबूत है कि और लोगों ने. भी ऐप्लाई किया था । क्या मिनिस्टर साहब इस बात की छानबीन करेंगे कि जिन्होंने ऐप्लाई किया था, उनको क्यों नहीं लिया गया?

कर्नल राव राम सिंह : आपकी यह बात कुछ हद तक दुरुस्त है क्योंकि जो पांच ऐप्लीकेशन्ज आई थी, उनमें से सिर्फ एक ऐप्लीकेशन को कन्सीडर किया गया । कारण यह कि बाकी के जो चार व्यक्ति थे, वे शर्तों को पूरा नही करते थे । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने लैक्चरारज की अप्वांयटमैंट के लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर रखीं है । जो उन शर्तों को पूरा करता है, असल ऐप्लीकेशन वही मानी जाती है, वैसे तो एक पोस्ट के लिए दो सौ, अढाई सौ और तीन सौ आदमी तक ऐप्लाई कर देते हैं ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो पोंस्टें खाली रही, उनकी री–एडवर्टाईजमैट के लिए क्या आपने बोर्ड को लिखा?

कर्नल राव राम सिंह : 35 पोस्टस खाली रह गई हैं क्योंकि उनके लिए कोई क्वा– लिफाईड ऐप्लीकैटंस अवेलेबल नहीं थे । हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि यू0जी0सी0 ने कालेज लैक्चरारज के लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें कुछ रिलैक्सेशन हो जाए, लेकिन यू0सी0 ने उसे स्वीकार नही किया । वैसे तो रूल यह है कि अगर हरियाणा में से कोई पोस्ट न भरी जा सकती हो, तो एडवर्टाईजमैंट करके आल इण्डिया वेसिज पर ऐप्लीकेशनज इनवाईट की जाएं लेकिन गवर्नमैंट सोच रही है 'कि इन इम्तहानों के बाद शायद कुछ ऐप्लीकेन्टस अवेलेबल हो जाए, जो इन शर्तों को पूरी करते हों । उसके बाद जो रिक्त स्वान हैं, इनको पूरा कर दिया जाएगा ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन पांच ऐप्लीकेशन्ज का इन्होने अमी जिक्र किया, उनमें से अन्य चार व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिए काल किया गया था?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इस बारे ने वे पहले बता चुके हैं ।

चौधरी पीर चन्द : मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि एक ही शड्यूल्ड कास्ट लिया गया । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि सारे हरियाणा में शड्यूल्ड कास्ट्स की रिजर्वेशन पूरी होती है या नहीं । अगर जवाब ना में है, तो क्या इसके लिए स्पैशल रिक्रूटमैंट करके कोटा पूरा करने की कृपा की जाएगी?

Mr. Speaker : Disallowed.

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय को इल्म है कि यह जो रिजर्वेशन है, इसमें दरअसल होता यह है कि खुशहाल हरिजन कैंडिडेट्स गरीब हरिजनों की कोस्ट पर सारा कोटा कन्ज्यूम करते हैं? यदि हां, तो क्या गवर्नमैंट के कंसीड्रेशन में कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत खुशहाल हरिजनों को हरिजनों के कोटे से डीलिस्ट कर दिया जाए, ताकि बाकी गरीब हरिजन उस कोटे को एनज्वाय कर सकें?

कर्नल रावराम सिंह : स्पीकर साहब, मेरे दोस्त का यह सवाल मेन क्वैश्चन से सम्बन्धित नहीं हैं । यह तो एक वाइडर चीज है कि अगर किसी हरिजन का सोशो–इकनौमिक स्टैण्डर्ड पर उठ जाता है तो उसको रिजर्वेशन कोटे में कंसीडर किया जाएगा या नहीं ।

Mr. Speaker : It is rather a suggestion for your consideration.

चौधरी हरिचन्द हूडा : स्पीकर साहब यह रिजर्वेशन का सवाल है और मन्त्री जी ने अभी बताया कि हरिजन कैडीडेट्स कंडीशन्व पूरी नहीं करते थे । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इन कंडीशन्ज को रिलैक्स नहीं कर सकते?

कर्नल राव राम सिंह : इस बारे में मैंने अभी अर्ज किया था कि रिलैक्सेशन के लिए यू 0जी0सी0 को लिखा था, लेकिन उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । इसमें एक बात जरूर है । अगर हम कालेज लैक्चरारज की. या स्कूल टीचर्ज की कंडीशन्ज में रिलैक्सेशन करते हैं, तो इसका असर आने वालो पीढ़ी पर पड़ेगा । अगर हम बिलों स्टैण्डर्ड के लैक्चरारज और मास्टरर्ज को रखते हैं, तो इससे बच्चों की पढ़ाई में अश्वय कमी रहे गी । इसलिए मेरा विचार यह है कि हमें कालेज लैक्चरारज का और स्कूल टीचर्ज का स्टेण्डर्ड इसी स्तर पर रखना चाहिए ।

चौधरी पीर चन्द : अध्यक्ष महोदय, 89 वैकेन्सीज में से 17 वैकेन्सीज शडयूल्ड कास्ट्स की बनती हैं । क्या मन्त्री महोदय बताएंगं कि ये वैकेन्सीज अभी खाली हैं, या नॉन शडयूल्ड कास्टस से भर दी गई हें?

कर्नल राव राम सिंह : मैंने अमी बताया झपा कि 35 वैकेन्सीज अथी खाली हैं ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा : क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्वेशन कास्ट बेलिज पर न करके इकनौमिक बेसिज पर करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : यह तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया था वाइडर पालिसी का सवाल है कि जिसका इकनौमिक स्टैण्डर्ड इम्प्रूव हो जाता है उसे रिजर्वेशन में से निकाल दिया जाए, या नहीं । बैकवर्ड क्लासिज की भी यही बात है । अगर कोई सोशो इकनौमिकली बैक– वर्ड रहता है उसके लिए कोई रिजर्वेशन हो या नहीं यह भी ओवरआल पालिसी का सवाल है और यह केवल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं ।

चौधरी गंगा राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा शिक्षा विभाग में बैकवर्ड क्लासिज के लिए कोई रिजर्वेशन है । अगर लूँ तो शिक्षा विभाग में फर्स्ट क्लास और सैकिण्ड क्लास पोस्टस पर बैकवर्ड क्लासिज के कितने व्यक्ति लगाए गए हें?

कर्नल राव राम सिंह : यह मेरे ख्याल से एक अलैहिदा सवाल है । इसके लिए अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे, तो जवाब जरूर पेश किया जाएगा ।

श्री लछमन सिंह : मिनिस्टर साहब ने अम्मी बताया कि 35 वैकेन्सीज खाली पड़ी हैं । क्या वे बताएंगे कि उनके खाली रहने से एजुकेशन पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है?

श्री अध्यक्ष : वे करे क्या, आदमी मिलते ही नहीं ।

कर्नल राव राम सिंह : एजुकेशन पर असर तो पड़ता है लेकिन जब ऐप्लीकैन्टस अवेले– बल न हों, तो एक किस्म की लाचारी होती है । इसके अलावा असर ज्यादा भी नहीं पड़ता, क्योंकि यह तो परसैन्टेज की बात है । जहां अनेक लैक्चरज हों, वहां अगर एक कालेज में एक वैकन्सी रहती हो, तो दूसरे उस काम को पूरा कर लेते हैं । (विध्न)

K.M. College, Narwana

***209. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over K.M. College, Narwana;

(b) if so, the time by which the aforesaid college is to be taken over by the Government; and

(c) whether Government propose to upgrade schools at villages Sacha Khera, Peepltha and Kalwan of Narwana Sub-Division ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) No.

(b) Question does not arise.

(c) Yes. The proposal is under consideration.

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे 'कि मैनेजिंग कमेटी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव उनको मिला है जिसमें मैनेजिंग कमेटी ने उनसे दरख्वास्त की हो कि कालेज को टेक ओवर कर लिया जाये?

कर्नल राव राम सिंह : इस वक्त हरियाणा के जो प्राइवेट कालेजिज हैं, उनमें से शिक्षा विभाग में काफी ऐप्लीकेशन्ज आ चुकी है, जो कि कालेजिज की मैनेजमैंट को गवर्नमैंट को हैण्ड ओवर करना चाहते हैं । इस वक्त इस किस्म की कोई प्रपोजल नहीं बनी है कि कौन से कालेज टेक ओवर किए जाएंगे और कौंन से नही किए जाएंगे । शिक्षा विभाग ने जो कमेटी बनाई थी उर्सकी रिपोर्ट आ गई है जिसको कंसीडर किया जा रहा है ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि कालेजिज को टेक ओवर करने के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है? क्या स्टाफ की कमी की वजह से, स्टाफ को पे न मिलने के कारण या मैनेजिंग कमेटी के प्रस्ताव की वजह से कालेज से टेक ओवर किया जाएगा ।

कर्नल राव राम सिंह : कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वह अन्डर कन्सीडेरशन है । इस वक्त तक तो कोई खास गाईड लाईन्ज मुकरर्र नहीं हुई हैं, लेकिन हाउस की इनफर्मेशन के लिए मैं इतना बता सकता हूं कि क्राइटेरिया, जिन लाइन्ज पर हम सोच रहे हैं, लगभग यह होगा । एक तो यह है कि यदि 2 0–2 5

किलोमीटर के आसपास दूसरा कोई कालेज नहीं है, तो उसको बन्द नहीं किया जाएगा । अगर मल्टिपलीसिटी आफ कालेजिज है, छोटे से एरिया में 8– 10 कालेज हैं, और किसी एक कालेज में एडमिशन सिर्फ 10 0, 150 या 50 ही है, और वह इकोनोमिकली वाएबल कालेज नहीं है, या ग्रोस.मिसमैंनेजमेंट हो रही है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो डोनेशन मिलता है या गवर्नमैंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन या ग्रांट मिलती है, उसका ग्रौस मिस्यूज हो रहा है, तो उसको टेक ओवर करने के बारे में सोचा जाएगा । तो यह कुछ जनरल गाईड–लाइन्ज हैं, जो फालो की जाएंगी ।

श्री मूल' चन्द मंगला : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि कालेज को टेक ओवर करने का जो डिसीजन अन्डर कंसीडेरशन है, वह अगले सैशन से पहले यानी अप्रैल से पहले पहले हो जाएगा, क्योकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : सैशन से पहले, मेरा अपना विचार है, होना मुश्किल है क्योंकि यी एक वास्ट क्रैश्चन है, जिसमें हरियाणा के कालेजिज का फयूचर डिसाइड करना है ।

एक सदस्य : ये कालेज सैशन से पहले पूछ रहे हैं, अपने सैशन से पहले नहीं ।

कर्नल राव राम सिंह : कालेज सैशन का टाईम भी बहुत कम रह रहा है । अगर कोई डिसीजन हो भी गया, तो यह ध्यान में रखा जाएगा कि लडकों का कोई नुक्सान न हो । उनको

इम्तहान की जो सुविधाएं होंगी, वे मिलेंगीं । जो भी फैसला होगा, वह इस सैशन के बाद ही लागू किया जाएगा ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया: क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो कालेज गवर्नमैंट के क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, उनको टेक ओवर किया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उन सबको सरकार लेगी या नहीं लेगा इस समय इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें फाइनैंशियल इम्प्लीकेशन्ज इनवॉल्वड है । सरकार के पास इस काम के लिए कितना पैसा है इस बात को ध्यान में रखा जाएगा । जहां तक गवर्नमैंट के टेक ओवर करने का सवाल है, इसके लिए गवर्नमैंट यह क्राइटेरिया रखेगी कि जिस जिस जिले में गवर्नमैंट का एक भी कालेज नही है, जैसे सिरसा और सोनीपत, उसको प्रैफैंस दी जाएगी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में एक ही कालेज है, उसको भी प्रैफैंस दी जाएगी ।

श्री फतेह चन्द विज : आपके पास मैनेजिंग कमेटी की दरखास्त आई हें, कि हमारे कालेज का काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है, इसे टेक–ओवर करें, क्या उन कालेजिज के काम को ठीक तरह से चलाने के लिए उनको इस साल कोई ग्रान्ट दी जाएगी? अगर नहीं दी है तो कब तक दे दी जाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : ग्रान्ट्स 45 परसैन्ट दी गई हैं । इस साल जितनी अमाउन्ट दी गई है वह पिछले साल से ज्यादा है

और आगे भी सोच रहे हैं कि जिन कालेजिज का मैनेजमैंट ठीक है और फाइनैंशियल डिफिकल्टी है उनको और अधिक ग्रान्ट देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सरकार कुछ प्राइवेट कालेजिज को बन्द करने की सोच रही है? अगर सोच रही है तो क्या उन कालेजिज के स्टाफ और जो प्रोफैसर हैं, उनके विषय में कुछ सोचा हे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, कालेजिज को टेक–ओवर करने के बारे में जो सरकार सोच रही है, वह बता चुका हूं । जहां तक स्टाफ का सवाल है, उनको कुल प्रो– टैक्शन दी जाएगी ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी नारायणगढ पिछड़ी हुई तहसील हैं । वहां पर तालीम की बहुत कमी है । वहां पर कोई भी सरकारी कालेज नहीं है । क्या शहजादपुर में जो प्राइवेट कालेज है, उसको भी सरकार टेक–ओवर करने का विचार रखती है ।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कन्सीडर कर रहे हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन जगहों पर पहले ही प्राइवेट कालेजिज अच्छा काम कर रहे थे, वहां पर गवर्नमैंट ने सरकारी कालेजिज खोल दिए हैं, क्या

ऐसे कालेजिज को देहातों में ले जाने की कोशिश की जाएगी? मिसाल के तौर पर करनाल का कालेज है ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक गवर्नमैंट कालेजिज का सम्बन्ध है, हरियाणा में कुल 14 कालेजिज हैं । मेरे ख्याल में ये तादाद बहुत कम हैं । किसी गवर्नमैंट कालेज को बन्द करने का सवाल नहीं है । जहां तक किसी कालेज की शिफटिंग का सवाल है वह इकोनोमिक प्वांयट आफ वयू से कोई उचित सजेशन नहीं है । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जहां पर गवर्नमैंट कालेजिज नहीं है, वहां पर कोई प्राइवेट कालेज को मैनेजमैंट हैण्ड ओवर करना चाहती है और 20–2 5 मील के एरिया में कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है तो, क्या उनको गवर्नमैंट कालेज बनाने में तरजीह दी जाएगी ।

चौधरी हरि चन्द हूडा : स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन नहीं है । मैं सजैशन दे रहा हूं । चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हर कास्टीच्युएंसी में दो लड़कियों के कालेज होंगे । आप जो ये प्राइवेट कालेजिज बन्द करने जा रहे हैं उनकी जगह पर हर कांस्टीज्युएंसी में दो लड़कियों के कालेज खोल दिए जाएं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी मेहर सिंह राठी : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन कालेजिज का इन्तजाम ठीक चलता है उनका आडिट सरकार के आडिटर्ज के जरिए कराया जाएगा? दूसरे वहां पर जो

स्टाफ भर्ती किया जाता है, उसकी भर्ती के समय यूनिवर्सिटी के या सरकारी अफसर इन्टव्यू में बैठाने की सरकार की कोई तजवीज विचाराधीन हैं?

श्री अध्यक्ष : यह सजैशन है ।

चौधरी गया लाल : क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि होडल कालेज में काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को आई हैं और उस कालेज के प्रोफैसर्ज को पांच– छरू महीनों से तनख्वाहे नहीं मिंत्री हैं, इस बारे में सरकार गौर करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : यह बात सरकार के अन्डर कन्सीडेरशन है । एक कालेज के बारे में कहना मुश्किल है । होडल कालेज की शिकायतों के बारे में इनक्वायरी की जा चुकी है और इनक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी हैं । वहां पर बहुत गड़बड़ चल रही है । सारा मामला गवर्नमैंट के अन्डर कन्सीडेरशन है ।

श्री हीरा नन्द आर्य: जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि हरियाणा में केवल 14 गवर्नमैंट कालेज हैं । क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही हैं कि जिस सब– डिवीजन में प्राइवेट या गवर्नमैंट कालेज नहीं हें, वहां पर कालेज स्थापित किया जाएगा और सरकार का कब तक ऐसा करने का विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : इस सवाल का जवाब आ चुका है । सब–डिवीजनों से पहले डिस्ट्रिक्टस में जहां पर गवर्नमैंट कालेज नहीं हैं, वहां पर कालेज खोले जाएंगे, जैसे सोनीपत और

सिरसा जिला हैं, पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक–एक कालेज खोला जाएगा, और फिर दो–दो खोले जाएंगे दूसरा कालेज जो होगा वह नैचुरली सब–डिवीजन में होगा । सारे हरियाणा में कालेजिज की इक्वीटेबल डिस्ट्रिव्यूशन कीं जाएगी ।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरानः क्या मन्त्री जी बताएंगे कि गुडगांव और महेन्द्रगढ़ कालेजिज में बी0एड0 की एडमिशन के टाईम पर चार–चार और पांच–पांच हजार रुपया ले कर एडमिशन दी जाती है, क्या सरकार उनका भी कोई बन्दोबस्त करने जा रही हे?

कर्नल राव राम सिंह : इस बारे में एग्जामिन किया जा रहा है । स्टेट में इस वक्त 18 प्राइवेट बी 0एड 0 कालेजिज हैं और दो कालेज गवर्नमैंट के हैं एक भिवानी में और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है । गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात है कि ये कालेज बहुत हैवी सब–स्क्रिप्शन लेकर एडमिशन देते है और इन कालेजिज ने एक किस्म की दुकानें खोल रखी हैं । इस बारे में गवर्नमैंट ने फैसला कर लिया है for gradual reduction in the intake for the B.Ed. Colleges.यानी इस साल 3600 बच्चों ने एडमिशन लिया था । पन्द्रह हजार लड़के आल–रेड़ी बी0एड0 ट्रेंड ऐम्प्लायमैंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं और 3600 उस लिस्ट में और चले जाएंगे । डिमाण्ड बिस्कूल नेगलींजिबल है । इसलिए इस साल 1800 लड़के लिए जाएंगे । इस तरह से स्केल डाउन करते लाएंगे और 500–600 को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी । ऐसा हम

कन्सीडर कर रहे है कि यह ट्रेनिंग केवल गवर्नमैंट कालेजिज में ही होगी ।

श्री देवी दास : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सोनीपत के किसी प्राइवेट कालेज की मैनेजमैंट कमेटी नेरैजोल्यूशन पास करके भेजा है कि सरकार हमारे कालेज कोटेक–ओवर कर ले या सोनीपत में कोई गवर्नमैंट कालेज बनाया जाये?

कर्नल राव राम सिंह : इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है ।

चौधरी संत कंवर : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसी प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपल को या मैनेजमैंट कमेटी को सरकार ने कोई चिट्ठी– लिखी है कि आपके कालेज को टेक–ओवर करने की सरकार की प्रपोजल है, इसलिए आप रिपोर्ट भेजें ताकि सरकार जायजा ले सके?

कर्नल राव राम सिंह : गवर्नमैंट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, वह उन कालेजिज में गई थी । उस कमेटी में प्राइवेट कालेजिज के मैम्बर भी शामिल किए गए थे । वह कमेटी हर जगह गई । उसने हर कालेज में जाकर वहां के मैनेजमैंटस में टीचिंग स्टाफ से मिलकर यह रिपोर्ट लिखी है ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जिन शिक्षा संस्थानों के मालिकों ने विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग देने के नाम पर लाखों रुपया कमाया है, और

उनमें हरियाणा जनता पार्टी के एक जनरल सैक्रेटरी भी हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : अगर कोई ऐसी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमैंट में ही नहीं किसी और डिपार्टमैंट में भी आती है और यह साबित हो जाता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, तो जनता पार्टी वर्ड बाउन्ड है कुरप्शन को बन्द करने के लिए, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मांगे राम गुप्ता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक प्राइवेट कालेजिज को टेक–ओवर करने की बात है, जो प्राइवेट विमैन कालेजिज हैं, उनको टेक–ओवर करने में कोई प्रैफैसं दिया जाएगा?

कर्नसं राव राम सिंह : यह सारा मामला विचाराधीन है । अलग–अलग केसिज के बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या वजीर साहब यह बताएंगे कि कैथल में जाट हाई स्कूल के खिलाफ एक रिपोर्ट भी आ चुकी है और वह साबित भी हो चुकी है, क्या उसक्एरू खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जाएगा? (विध्न)

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो कालेजिज के बारे में है । (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू.: क्या उम्रके खिलाफ कोई हेक्शन लेने की तजवीज है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

Prices of Bricks

***222. Chaudhri Sher Singh :** Will the Minister for Food and Supplies be **pleased** to state—

(a) the extent to which the prices of bricks increased or decreased after lifting the control on bricks by the Haryana Government ; and

(b) whether it is a fact that the Government supplies coal to the owners of Brick kilns on control rates; if so, the justification for lifting the control on the bricks ?

खादय् एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमन्रू वर्मा) :

(क) ईंटों पर से भाव तथा वितरणनियन्त्रग 1 8— 1 1— 77 से हटा लिया गया था । भाव नियन्त्रण उठने के पश्चात् प्रथम श्रेणी की ईंटों के भाव 10 रुपए से 35 रुपए प्रति ईंटें बढ़े हैं ।

(ख) हां जी । यह विचार किया गया था कि ईंटों की कीमतों पर से नियन्त्रण हट जाने से इनकी उपलब्धी बढ़ेगी और इनकी क्वालिटी में भी सुधार आएगा क्योंकि भट्टे वालों का आपसी मुकाबला होने के कारण उपभोगता ईंटें अपनी मर्जी के भट्टे वाले से खरीद सकेगा । कम पैसों के बिल पर सप्लाई करने जैसी

कुरीतियां दूर होंगी और सरकार को सेल्ज टैक्स तथा आयकर की शक्ल में लाभ होगा ।

चौधरी शेर सिंह : क्या मन्त्री साहिबा यह बताने की कृपा करेंगी, जैसे कि उन्होंने अभी यह बताया कि 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक भाव बडे है, उनका दोबारा ईंटों पर कन्ट्रोल करने का इरादा है? इन्होंनें साथ यह भी कहा है कि भट्टों को कोयला कन्ट्रोल रेट पर दिया जाता है, मैं उनसे यह भी जाना चाहता हूं कि क्या उनको आवश्यकता अनुसार पूरी मात्रा में पर्याप्त कोयला भी दिया जाता है या नही?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : कोयले के बारे में केन्दीय सरकार के 0र्जा मन्त्री से काफी पल–व्यवहार किया गया । उन्होंने यह बताया है कि पिछले दिनों कोलेरीज के अन्दर ही कोयले की प्रोडक्शन कम हुई है लेकिन अब उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि आए महीने 4375 वैगने पूरी मिला करेंगी । जहां तक भाव बढ़ने का ताल्लुक है, अगर भाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो हम उसे फिर से कन्ट्रोल कर देंगे ।

चौधरी राम किशन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगीं कि यह बात उनकी जानकारी में है कि इस वक्त हरियाणा के अन्दर ईंटों के भाव 15 क्य 180 रुपए प्रति हजार हैं? अगर हैं तो क्या उसे फिर से कन्ट्रोल करने का इरादा है?.

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा :. हम हर 5 दिन के बाद स्टेट के डी 0एफ0 सी 0 से रिपोर्ट मंगाते हैं कि किस जिले में कितना भाव है । हमारी रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी किले में 130 रुपए से ज्यादा भाव नहीं गया है ।

श्री मूल चन्द : जैन मन्त्री महोदया ने यह बताया है कि कोलेरीज में कम कोयला प्रोडक्शन होने की वजह से हरियाणा को कम कोप ला मिला है । क्या मन्त्री महोदया की नालेज में यह बात है कि 290 रैक तो हमारे पास आए, लेकिन 193 रै कं वैगन न अवेलेबल होने की वजह से नहीं आ सके? हरियाणा सरकार, कलकत्ता में जो रेलवे का मूवमैंट आफिसर है, उसके साथ को–आर्डिनेशन नही कर सकी, इसलिए हरियाणा को जो 193 रैक्स मिलने थे, वह न मिल सके, क्या उन्हें यह पता है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : वैगन मूवमैंट के बारे में हमने रेलवे मन्त्री को भी बार– बार लिखा है । जैसे कि मैंने अभी बताया है कि उन्होंने यह अश्वासन दिलाया है कि आगे से वैगन आपको पूरे मिलेंगे, और उससे कोयला का कोटा पूरा मिलने की पूरी सम्भावना है ।

कंवर राम पाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी, जैसे कि उन्होंने अभी यह बताया है कि कन्ट्रोल हटने से कुछ कुरीतियां दूर होंगी और सरकार को सेल्ज टैक्स तथा आयकर की शक्ल में लाभ होगा, क्या सरकार को अपने

कामों के लिए ईंटें खरीदते वक्त कुछ ज्यादा भाव देना पड़ेगा और उससे सरकार को खर्च कुछ ज्यादा करना पड़ेगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : नहीं, इतना ज्यादा नही करना पड़ेगा ।

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदया ने यहां पर यह कहा है कि हमने रेल मन्त्री को बार बार लिखा है, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा ने जो कोल कन्ट्रोल आर्डर । मई, 1977 में बनाया था और उस आर्डर के अधीन जो एजेंट मुकरर्र किए थे, और उनको . जो लाईसैस देने की प्रथा अपनाई थी, क्या उन एजेंटों ने रेलवे मूवमैंट आफिसर से को–आर्डिनेशन नही किया? मैं उनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उस कोल कन्ट्रोल आर्डर की वजह से हरियाणा को 193 रैक्स आफ कोल्ज का घाटा उठाना पड़ा, क्या यह बात – ठीक नहीं है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : हमने कोल मरचौन्ट्स की एक मीटिंग बुलाई थी । उनसे इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था । उन्होंने इस बात से इन्कार किया । उन्होंने भी यही कहा, जैसे कि हमने बार–बार यह कहा है कि कोलेरीज में प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमें कोयला पूरा नहीं मिल पाया है ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या वजीर साहिबा बताएगी कि आप कितने परसैन्ट कमीशन या प्रोफिट कोयला एजेंट को देते

हैं और कितने भाव को सरकार मेंहगा समझती है और कितने भाव को रीजनेबल समझती हे?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्लैक कोल के अन्दर हम 4 प्रतिशत और सौफ्ट कोल के अन्दर हम 6 प्रतिशत?इतक प्रोफिट देते हैं । ईंटों के भाव के बारे में आप जरा अपने प्रश्न को फिर से दोहरा दीजिए?

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या मन्त्री महोदया बताएगी कि ईंटों के कितने भाव को सरकार उचित समझती है और कितने भाव को सरकार मंहगा समझती है? मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 80 रुपए प्रति हजार रुपए का खर्चा उनका आता है और अगर वे 120 रुपए के भाव पर भी बेचे' तो भी उनको 100 प्रतिशत प्रोफिट मिल जाता है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा :. इस बारे में तो हाउस जैसे चाहेगा, हम वैसे ही कर देंगे । हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है, जिसमें आई0पी0एम0 और फाइनैसं मिनिस्टर भी शामिल हैं । हम उस कमेटी में निर्णय ले लेंगे । जो भी वह निर्णय करेंगे, हम उसे लागू करेंगे । जनता का ध्यान पहले रखा जाएगा अगर कन्ट्रोल करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसके निर्णय के मुताबिक शीघ्र ही कन्ट्रोल कर देंगे ।

साथी अयोध्या प्रसाद : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगीं कि ईटों के बनाने में प्रति हजार कितनी लागत आती है ।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : जो हमारी बिक क्लिन ओनर्ज के साथ मीटिंग हुई थी, उसके अन्दर उन्होंने यह बताया था कि 123 रुपये प्रति हजार के हिसाब से उनका खर्चा आता है । लेकिन जब हमने यह डी–कंट्रोल किया तो 123 रुपये तक तो नहीं, ईंटों का भाव प्रति हजार का 95 से लेकर 110 रुपये तक गया है ।

चौधरी हुकम सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने यह माना है कि ईटों की कीमतें चढी हैं और आप सब को पता है कि आज बाजार में ईटों का भाव 15 क्य 160 रुपये से कम नही है, क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार को उसे फिर से कन्ट्रोल करने में क्या दिक्कत पेश आ रही हे?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है । यह तो एक ऐक्सपैरीमैंट किया गया है । जैसे ही हम दिक्कत समझेंगे, उनको फिर से कन्ट्रोल कर देंगे । परन्तु एक बात मैंने आरम्भ में भी स्पष्ट की थी कि पिछली सरकार ने 85 रु 0 कंट्रोल रेट तय किया हुआ था । वह कागजों में ही था, सरकार को अवश्य थोड़े काम के लिए 85 रु0 मिलती थी, आम जनता को 150, 180 रु0 से कम नही मिलती थी । रसीद 85 रु 0 की और

जनता 150 रु 0 देती. थी, सरकार को टैक्स का भी घाटा रहता था इसलिए ईंटों को डो–कंट्रोल किया गया है ताकि मार्केट में कम्पीटीशन हो । इस भाव को देखते हुए जनता के लिए डी–कंट्रोल के बाद कीमतें बढ़ी नहीं, सरकार के लिए थोड़ी बढ़ी हैं ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि ईटों से कंट्रोल उठाने की वजह यह थी कि जनता पार्टी ने भट्ठे वालों से इलेक्शन में चन्दा लिया था?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : यह बिल्कुल गल्त बात है ।

श्री रण सिंह मान : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि नियन्त्रण हटाना जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध नहीं हे?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : किसी मी डेमोक्रेसी के अन्दर कन्ट्रोल जारी रखना किती भी पार्टी की नीति नहीं होती । कंट्रोल हटाकर हमने एक्सपेरीमेन्ट किया है जिससे कम्पटीशन में लोगों को सस्ती ईंटें उपलब्ध हो सके ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : : अबैंसिज कमेटी की मीटिंग में जनता की फीलिंग यह थी कि ईंटों के भाव ज्यादा बढ चुके हैं । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि दोबारा कंट्रोल करने से आप कोई प्रेशर तो महसूस नहीं कर रही हें?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं भट्ठे वाले तो यह कहते हैं कि चाहे हमसे टेन्डर इन्वाइट कीजिए और हम 120 रुपए के भाव घर पहुंचा रहे हैं । इसलिए बेशक कंट्रोल कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कोलरीज से जो कोयला लाया जाता है वह प्राईवेट आदमी जो कोल एजेन्ट्स होते हैं उनके द्वारा लाया जाता है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार इस– एजेन्सी को अपने हाथ में नहीं ले सकती?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, भारत कोल कम्पनी को हमने दो डिस्ट्रिक्टस दिए कि वह लोगों को कोयला सप्लाई करे । अगर इसमें हमें सफलता मिंत्री तो हम सारी जगह ऐसा ही कर देंगे ।

चौधरी गुलजार सिंह : स्पीकर साहब, हरियाणा में कोयले की कमी है और उसकी वजह से भट्ठे वालों को ब्लैक में कोयला खरीदना पड़ता है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या कोयला की कमी की बात उनके नोटिस में है और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कोई कदम उठाये जा रहे हें?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, यह चीजें हमारे नोटिस में है और हमारे मुख्य मन्त्री महोदय भारत सरकार के 0र्जा मन्त्री को बारबार लिख रहे हैं कि हरियाणा को जितना

कोयला एलोकेट हुआ है वह पूरा मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयास जारी है ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, भट्ठा कमाने के लिए महकमा की तरफ से कुछ नियम निर्धारित है कि भट्ठा स्कूल से इतना दूर होना चाहिए, बाग से इतना दूर होना चाहिए । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि कितने भट्ठे वाले इस हिदायत का पालन नही कर रहे हैं और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जाएगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इस सरकार ने जो क्राईटेरिया तय किया है उसको पूरा करने पर ही भट्ठे का लाइसैंस दिया जाता है । जिस डिसटेन्ट के आधार पर पिछली सरकार ने लाइसैंम दिए थे उनको हम इस समय बन्द तो नहीं कर सकते लेकिन जब उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो उनको हमारे द्वारा तय किया हुआ डिस्टेन्स का पालन करना पड़ेगा, अगर वे नहीं करेंगे तो उनके लाइसेंस केन्सिल कर दिए जाएंगे ।

चौधरी राम किशन : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया कि 120 रुपए फी हजार ईन्टे बिक रही हैं, यह बिल्कुल गल्त बात है । डिस्ट्रिक्ट जींद में 150 रुपए या 160 रुपए फी हजार बिक रही हैं । क्या मन्त्री महोदया सदन में यह विश्वास दिलाएगी कि आईन्दा ईन्टे 120 रुपए हजार से ज्यादा नही बिकेंगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, मैंने यह कहा था कि एक दो जिलों में ईन्टें 120 रुपए प्रति हजार भट्ठे पर हैं । यह नहीं कहा था कि घर पर 120 रुपए हजार के हिसाब से सप्लाई करते हैं । घर पर पहुंचाने का भाव ज्यादा हो सकता है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करगी कि डि–कन्ट्रोल करने से क्या सरकार को नु क्हान नहीं होगा क्योंकि पहले सरकार को सड़क बनाने तथा मकान बनाने के लिए ईन्टे सस्ती मिल जाती थी और अब डिकन्ट्रोल से महंगी मिलेंगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इसलिए तो डि कन्ट्रोल किया है । पहले 85 रुपए हजार के भाव से सरकार जो ईंटें खरीदती थी वह इतनी अच्छी नहीं होती थीं । अब सरकार कम्पीटीशन से अच्छी ईंटें खरीद सकेगी । सरकार अपने से अधिक जनता का ध्यान रखना अपना कर्तव्य समझती है ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदया को पता है कि कोयले की एक वेगन पर पांच से दस हजार तक की ब्लैक है और भट्ठे वाले कहते हैं कि वे कोयला ब्लैक में खरीदते है इसलिए उनको 160 रुपए हजार के हिसाब से ईंटें बेचनी पड़ती हैं ।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इस तरह की अगर कोई बात है तो आप हमारे नोटिस में लाएं हम विजिलेन्स से इसकी इंक्वायरी करवा लेंगे ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया है कि रेल वेगन्ज की कभी है और सरकार ने हिन्द सरकार को इस बारे में लिखा है । स्पीकर साहब, पिछले महीने यानी जनवरी में कलकत्ता में डायरेक्टर रेल मूवमेन्ट ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हरियाणा के भी नुमाईद थे । डायरेक्टर रेल मूवमेन्ट ने यह शिकायत की कि कोल कन्ट्रोल आर्डर के नीचे जो कोल ऐजेन्ट मुकर्रर किए थे उन्होंने कोल लिफ्ंट नहीं किया । यह शिकायत प्रान्त के नुमाईदों से की गई थी । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह ठीक बात है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, मेरे पास श्री पी0 रामचन्द्रन जो 0र्जा मन्त्री हैं का एव है । उसमें लिखा है–

" For some time past, the production of coal has suffered a set back due to shortage of explosive and power and consequently dispatches of such coke to the various States including Haryana have not been to the required extent . . .

स्पीकर साहब, मैं कैसे मान लूं कि कोयला न उठाने की कोई शिकायत की गई थी । यह पत्र 10 जनवरी को आया है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदया बताने के। कृपा करेंगी कि डि–कन्ट्रोल होने के बाद सेल्ज टैक्स कितना मिला है । कम मिला है या ज्यादा मिला है । जिस तरह सेन्टर ने सरसों के तेल के बारे में एक लिमिट फिक्स कर दी कि दस रुपए से

ज्यादा नहीं बिक सकेगा, क्या उसी तरह हमारी सरकार भी ईंटों के बारे में करेगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : यह विचाराधीन है, यह अलग प्रश्न है । यह बात मुझे लिखकर दें ।

सरदार सुखदेव सिंह : अभी बताया गया कि भट्ठे वालों का 123 रुपए हजार ईटों की प्रोडेक्शन का खर्चा आता है लेकिन पंजाब में सौ रुपए हजार ईटे बिक पी है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसका क्या कारण हैं?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : यह कोई प्रश्न नहीं है?

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि कोयले की कमी की वजह से क्या कोई भट्ठा बन्द हुआ है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : बन्द तो नहीं हुआ है लेकिन दिक्कत अवश्य महसूस कर रहे हैं ।

New Roads Constructed

***228. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise new roads and bridges constructed in the State after the formation of Janata Government together with mileage thereof; and

(b) whether there is any scheme under

consideration of the Government to construct more new roads and bridges in the State ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) वांछित सूचना का विवरण सदन के पटल पर पेश है ।

(बी) हां

STATEMENT

District-wise new roads and bridges constructe d in the State after the formation of Janata Government togetherwith mileage thereof.

Sr. No.	Distt.	Roads sanction- ed after forma- tion of Janata Govt. and length metalled against these schemes upto 31-12-77		Road Bridges length me- tailed from 1-7-77 to 31-12-77 against works which were in progress when Janata Govt. took-over		Bridges sanctioned after Janata Govt. over and their progress		Bridges completed after Janata Govt. took over, but were in progress before 1-7-1977.	
		No.	Length metall (Kms).	No.	Length metalled (in Kms.)	No.	Progress	No.	Progress

	ed						
1. Ambala	6	—	35. 47	2	Tenders under examination	1	Completed
2. Bhiwani	9	1.42	16.24		—	—	—
3. Gurgaon	—	—	28.27	1	—	—	-
4. Karnal	4	—	21.52	—			Completed
5. Jind			15.41	—		—	
6. Mohindergarh	—	—	16.03			-	
7. Hissar	32	23 .15	41.04		—		—
8. Rohtak	1	—	3.95	—	—	—	-
9. Sonepat	1	—	3.54	—	—	—	-
10. Kurukshetra	5	—	42.51	2	One under construction & tenders called for, second	—	-

11. Sirsa	18	12.90	22.56	1	Under construction	—	-
Total :	80	37.47	246.54	6	—	2	—

चौधरी खुरशीद अहमद : सी कर साहब, जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई उसमें सड्कों की डिटेल भी है और मन्त्री महोदय के मुताबिक 80 सड़कें जनता सरकार ने सैंक्शन की हैं । मैं आपके न नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं और मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि किस क्राईटेरिया के तहत ये 80 सड़कें बनाई गई हैं—गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ में निल, रोहतक और सोनीपत में एक—एक, करनाल और जींद में चार—चार, कुरुक्षेत्र में 5, अम्बाला में 6, भिवानी में 9, हिसार में 3 2, और सिरसा में 18 । 80 सड़कों में से 59 सड़कें तो भिवानी, हिसार और सिरसा में हैं और बाकी सारे हरियाणा के लिए केवल 21 सड़कें हैं । यह कौन सा इन्साफ पसन्दाना रवैया सरकार ने अख्तियार किया है । ये सारी 80 सड़कें ही वहां क्यो न बनवा दी । क्या मन्त्री महोदय इस चीज को कलीयर करने की कृपा करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने जो सवाल का जवाब पढ़ा उसका एक कालम ही पढ़कर सुना दिया, तीसरा कालम इन्होंने पढ़ना गवारा नही किया । तीसरे कालम से साफ जाहिर है कि जनता सरकार बनने के बाद' जो मैटल्ड रोडज बनाई गयीं वे इस प्रकार हैं—अम्बाला जिला 35.47

किलोमीटर, भिवानी 16.24 किलोमीटर, गुडगांव 28.27 किलोमीटर, करनाल 21. 52 किलोमीटर, जींद 15.41 किलोमीटर, महेन्द्रगढ़ 16. 03 किलोमीटर, हिसार 41.04 किलोमीटर, रोहतक 3. 95 किलोमीटर, सोनीपत 3.54 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र 42.51 किलोमीटर, सिरसा 22.58 किलोमीटर ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, मैंने जो सप्लीमैंट्री किया वह यह थाकि कालम 1 में मिनिस्टर साहब ने जो सड़कें दी हैं, वे हमारी जनता सरकार ने ओथ लेने के बाद सैक्शन की हैं । यह जो कालम उन्होंने पढ़ा है, यह उन सड्कों की लैन्थ है जो जनता सरकार के फार्म होने से पहले कान्टीन्यूयिंग वक' थे । मेरा सवाल तो यह था कि नई सरकार की पालिसी तो सैक्शन के टाईम में आती है । नई सरकार ने कितनी सड़कें सैक्शन की हैं, ये तो कान्टीन्यूड सड़कें हैं यह तो मैंने केयरफुली देख लिया था । यह' जो काम है यह तो पुरानी सरकार की बनाई हुई सड्कों – को मैटल करने का है । नई सरकार की सैशक्न रोडज ' जो हैं,' उनका– कालम 1 में दिया है गया । ज ओं कालम 3 में सड़कों की मैटलिंग दिखाई गई है वह तो पहले ही सैक्शन थीं । कालम 2 की मैटलिंग जो है, वह मैं पढकर सुना देता हूँ । भिवानी में 9 सड़कें सैक्शन्ड थीं, उनमें से 3 1– 1 1– 77 तक 1 42 किलोमीटर मैटलिंग की गई । हिसार में 23 रू 1 5 किलोमीटर हुई और सिरसा में 12 रू 9 0 किलोमीटर– रोडज की मैंटलिम हुई और बाकी हरियाणा निल ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जिस समय जनता पार्टी ने ओथ ली थी, उस वक्त विलेज वाईज सड्कों की पोजीशन 70. 8 प्रतिशत आती थी । 1— 4— 77 से 1— 2— 78 तक 188 गांवों —की सड़कों के कन्टैक्ट करने के बाद अब सड्कों की परसैटेज 80. 3 प्रतिशत हो गई है । जिले वाईज जिन गांवों को रोडज से कनैक्ट किया गया है, वे इसप्रकार हैं—भिवानी 19. 4 प्रतिशत, सोनीपत 88 9 प्रतिशत, जीद 87 4 प्रतिशत, रोहतक 83. 9 प्रतिशत, हिसार 78. 5 प्रतिशत, महैन्द्रगढ 78 8 प्रतिशत, करनाल 78 5 प्रतिशत, गुड़गांव 76. 1 प्रतिशत, अम्बाला 70. 2 प्रतिशत, कुरुक्षेत्र 89 0 प्रतिशत, सिरसा 6 6. 9 प्रतिशत और जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो सारे हरियाणा की परसैटेज थी, वह यह है भिवानी 89.4 प्रतिशत, सोनीपत 86 से 87. 8 प्रतिशत, जीद 87.4 से 92.3 प्रतिशत, रोहतक 83.9 ' से 85.1 प्रतिशत, हिसार 78.5 से 84.4 प्रतिशत, महेन्द्रगढ़ 78.6 से 80. 7 प्रतिशत करनाल 78. 5 प्रतिशत से 82.7 प्रतिशत, गुड़गांव 76.1 प्रतिशत से 77. 8 प्रतिशत, अम्बाला 70. 2 से 71.5 प्रतिशत, कुरुक्षेत्र 690 से 73. 8 प्रतिशत, सिरसा 66 9 से 70.3 प्रतिशत ।

अब मैंबर साहिबान नोट फरमाएंने कि जनता पार्टी ने जब ओथ ली थी उस वक्त भी सिरसा सबसे नीचे था पौर आज भी सबसे नीचे है ।

चौधरी संत कंवर : स्वीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई में मैटल्ड रोडज की जो लम्बाई बताई है, वह कालम

3 के अनुसार 3. 95 है और कालम 1 में निल' दिखाया है । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जब चौधरी सुरेन्द्र सिंह के पिता थे तब भी हमारे रोहतक जिले की ऐसी ही स्थिति थी और आज भी वही हाल है । इसके क्या कारण हैं?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने जो फिर्ग्ज अभी पढ़कर सुनाई, हो सकता है किवे ठीक हों । क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि जो सडके इस साल में सैक्शन्ड की गई है, उनका क्या क्राइटेरिया रखा है । हिसार की जो 32 फिर्ग्ज बताई हैं उसके बारे में भी मिनिस्टर साहब बता दें कि– उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया गया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब यह जो सडकें हिसार में सैक्शन्ड की गई हैं, ये वो सडकै हैं जो पंजाब को हरियाणा से मिलाती हैं । दोनों स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्ज ने आपस मैं बैठकर यह फैसला किया था दोनों स्टेट्स में आने जाने की सुविधा के लिए इन सड़कों को प्रायर्टी दी जाय और मक्के आफ दी सउके' जो हिसार में बनाई गई हैं वह पंजाब के बार्डर के साथ लगती हैं । सरदार लछमन सिंह. अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया हैकि हिसार में पंजाब और हरियाणा बार्डर्ज को मिलाने के लिए सड्कों को प्रायर्टी दी गई है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब ने कालका के पास करोरा विलेज तक तो अपना काम खत्म कर दिया

है पर हरियाणा ने इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इसके क्या कारण हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसको बनाने के लिंए हैम जल्द ही कदम उठा रहे हैं ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि मुजफ्फर पुर जिले के गांव जलालपुर, पत्थरगढ़, नवादा, राना माजरा, बेसकगढ वगैरह 1961 में यमुना का रुख बदलने के कारण हरियाणा में शामिल हो गए हैं, वहां पर भी सड़कें बनाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हरियाणा में अब तक 8731 गांवों में से आज के दिन तक 5300 गांवों की सड़कें बन चुकी हैं, 1371 याव अभी बाकी हैं, अगर इन सारे गांवों को एक–एक रोड से जोड़ा जाये, तो हमें 32 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास अगले साल में इतना बजट नहीं है इसलिए 'ए' और 'बी' की कैटेगरी की जो सड़कें हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है ।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान : स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि हिसार के इलाके को पंजाब के साथ मिलाने के लिए वहां पर सड्कों को प्राथमिकता दी गई है क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गुड़गांव का जो इलाका है वह राजस्थान

और दिल्ली बार्डर से लगता है, क्या वहां पर भी सड़कें बनाने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इन सड़कों को भी अगले साल इन्टर कनैक्ट कर दिया जाएगा । बशर्ते कि दूसरी स्टेट्स वाले भी ऐसा करने को तैयार हों ।

कंवर राम पाल सिंह : मन्त्री महोदय ने जैसे अभी बताया कि हिसार जिले की जिन सड्कों को प्रायरर्टी दी गई है वह पंजाब के साथ इन्टर स्टेट सड़के होने की वजह से दी गई है । जो सड़कें यू 0पी0 को इन्टर कुनैक्ट करती हैं उनको प्रायरटी क्यों नहीं दी गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसलिए नही दी गई क्योंकि यू 0पी0 सरकार इससे सहमत नहीं थी ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हमारे गुडगांव जिले में पलवल और बल्लभगढ तहसील में 30 गांव जमना नदी के दूसरे पार हैं, क्या सरकार उन गांवों को सड्कों की सुविधा देगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले ही अर्ज किया है कि नई सड़के बनाने के लिए अगले साल 'में हमारे पास पैसा बहुत ही कम है । जो 'ए' और 'बी' कैटेगरी की सड़कें हैं यॉ जो मैरून्ड विलेंजिंज में सड़कें प्रोवाईड की गई हैं या जो फ्लड की वजह से सड़कें डैमेज हो गई हैं, उन पर खर्च करेंगे ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में जो सड़कें अभी पक्की नहीं हुई हैं, उनकी जिलावार लैन्थ कितनी–कितनी हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जिलावार फिगर तो इस समय नही हैं, लेकिन टोटल जो' सड़कें कम्प्लीट हो चुकी हैं, उनकी लैन्य 15917 किलोमीटर हैं ।

चौधरी रिजक राम : पिछले सैशन में मन्त्री महोदय ने ऐलान किया था कि जो गैप्स हैं, उनको प्रायर्टी देकर पहले उन पर काम शुरु किया जाएगा । तो क्या सोनीपत, रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा दूसरे जिलों में इस साल उन मिसिंग लिंक्स पर कोई काम किया गया है? दूसरा सवाल यह है कि हिसार और सिरसे में सारेविलेजिज पक्की सड़कों से कनैक्ट करने का काम हो रहा तो क्या बाकी हरियाणा का भी ध्यान रखा जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक गैप्स का ताल्लुक है, उनकी लैन्थ काफी माइलेज में आ जाती है जो कि लगभग 'ए' तथा 'जी' कैटेगरी में आ जाती है, हम उनको टॉप प्रायरिटी देंगे । दूसरी बात जो सोनीपत के बारे में है उसके बारे में निवेदन यह है कि मैंने जो स्टेटमैंट पढ़ी थी उसमें बताया था कि हिसार और सिरसा अब भी नीचे कुंए । मैंबर साहब चिन्ता न करें सब जगह बराबर काम चलेगा ।

राव राम नारायण : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सालावास हल्के में लिंक रोडज सब से कम हैं क्या वहां के लिए कोई सड़क सैक्शन की गई है?

Shri Verendar Singh : Without prior notice this cannot be replied.

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा बनने के बाद और जनता सरकार के टेक–ओवर करेंने से पहले टोटल रोडज पर कितना खर्च हुआ और उसमें से अम्बाला किला पर कितना खर्च हुआ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसके लिंए सैप्रेट न ओटिस चाहिए । वैसे मैं आपको बाहर यह फिगर बता सकता हूं ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कि जमना, नदी के वजह से जो गांव हमेशा ही मैरून्ड रहे हैं, चाहे वे' गुड़गांव जिले के हैं और चाहे सोनीपत के तो क्या उनको टाप प्रायरिटी दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैरूड विलेजिंज को राहत देने के लिए पक्की सड़के बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान उनकी ही स्टेटमैंट की तरफ दिलाना चाहता हूं । उसमें जो उन्होंने 80 सड्कों का जिक्र किया है, उनमें से जो कम्प्लीट हुई हैं, वे भिवानी, हिसार और सिरसा इन तीन जिलों पर ही

तवज्जो दी गई है । भिवानी की 9 सड्कों में से 1.42 किलोमीटर भाग मैटन्ड की गई है और हिसार की 32 सड्कों का 23.15 किलोमीटर भाग मैटल्ड किया गया है तथा सिरसा की 18 सडकों का 12.90 किलोमीटर भाग मैटल्ड किया गया है । इन तीन जिलों के अलावा और किसी भी जिले में एक कौड़ी भी खर्च नहीं की गई है । इसका मतलब यह है क जैसे पुरानी सरकार सिर्फ भिवानी पर तवज्जो देती रही थी उसी– प्रकार यह सरकार हिसार और सिरसा पर तवज्जो दे रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह 'गल्त बात है । मैंने इसलिए कहा था सवाल पूछते वक्त कालम नं. 3 का ध्यान रखा जाये । ये वह सड़कें हैं, जो सैक्शन की गई हैं और सैक्शन होने के बाद काम हुआ है । जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो सड़कों को मैटल करने का काम किया गया वह कालम नं. 3 में दिखाया गया है ।

श्री मूलचन्द जैन : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब कन्फ्यू कर रहे हैं ।

मास्टर शिव प्रशाद : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अम्बाला शहर विधान सभा क्षेत्र के जो गांव किसी भी लिंक रोड़ से जुड़े हुए नही है, क्या वहां कोई लिंक रोड बनाने का सरकार का इरादा हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने निवेदन किया या कि नई सड़कें बनाने के लिए हमारे पास अगले वित्त वर्ष में भी पैसे की कोई सम्भावना नहीं है अगर 'ए' तथा 'बी' कैटेगरी की कोई सड़क होगी, तो उसका जरूर ध्यान रखा जाएगा ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि दिल्ली के साथ–साथ जो सड़कें हैं, वह दूसरे राज्यों ने तो अपनी हद में बना दी हैं लेकिन हमारी तरफ से नहीं बनी हैं, उनको कब तक बना दिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हर आदमी चाहता है कि उसके हल्के 'के अन्दर ज्यादा काम हो । मैं अर्ज करता हू कि जितनी– भी इन्टर कनैक्टड रोडज हैं, उनके बारे में हम दूसरी स्टेट्स को एग्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर दूसरी स्टेट्स एग्री कर जाती हैं, तो हम उनको बनवा देंगे ।

श्री बलदेव तायल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इन सड्कों को बनाने से पूर्व टैक्नीकल सैक्शन ले ली गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जो मौजूदा सड़कें हैं, उनकी टैक्नीकल सैक्शन ले ली गई हैं ।

स्वामी आदित्य वेश : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि 80' सड्कों में से 50 केवल हिसार और सिरसा के लिएसैक्शन कीगई हैं,तो इनमे से गांवों' के लिए कितनी सैक्शन कीगई है. ।.

श्री वीरेन्द्र सिंह : ये तो सब गांवों की ही सड़कें हैं । शहर कौन से हैं इनमें ।

स्वामी आदित्य वेश : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस पर आधे घंटे का समय और दे दें ।

श्री अध्यक्ष : इस पर सकल तो बहुत हो चुके हैं और उनके जवाब भी मिल चुके हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि हिसार और सिरसा के जिले पहली सरकार ने इग्नोर रखे (विघन एवं शोर) और उस समय वहां सड़कें कम बनीं इसलिए इन जिलों को दूसरों के बराबर लाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, मैं समझता हूं वह उचित है और जो अभी भी काम बचता है क्या मन्त्री जी उसको शीघ्र पूरा करवाने की कोशिश करेंगे? (शोर)

Mr. Speaker : The question hour is over.

तारांकित प्रश्न संख्या 228 पर आधे घण्टे की बहस की माँग

स्वामी अग्नि वेश : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा गम्भीर है और प्रत्येक विधायक, प्रत्येक माननीय सदस्य इस प्रश्न पर प्रश्न पूछने के लिए 'उत्तेजित है । इस विषय पर मिनिस्टर

साहब ने जो तथ्य रखे हैं, उनसे और कन्फ्यूजन बढ़ गया है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आधे घंटे के लिए डिस्कशन मन्जूर की जाये ।

Mr. Speaker : What do you say, Mr. Verendar Singh ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मुझे कोई एतराज नहीं ।

Mr. Speaker : There will be half-an-hour discussion sometime. I will allot the time, provided इसका नोटिस रूल्ज के मुताबिक दो मैंबरों से दस्तखत होकर आए ।

नियम 45 के अधींन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Sugar Mills in the State

***260. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of sugar mills in the State as on 31-3-1977;

(b) the total number of sugar mills which are proposed to be set up in the State in the near future; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a sugar mill at Kaithal ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क)पांच

(ख) पांच

(ग) कैथल भी उन स्थानों में से एक स्थान है, जहां पर शूगर मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

Government Middle/High Schools

***249. Chaudhri Sant Kanwar :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of Government Middle/High Schools in District Rohtak at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade schools from Primary to Middle and from Middle to High in District Rohtak, particularly in Hassangarh Constituency of District Rohtak ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) (1) माध्यमिक पाठशालाएं 70

(2) उच्च पाठशालाएं 121

(बी) जी हां ।

Approach Roads in Meham Constituency

***270. Chaudhri Har Swarup Bura :** Will the Minister for Irrigation **and Power** be pleased to state—

(a) the names of villages which have no approach roads in Meham Constituency and the time by which these are likely to be connected with the approach roads; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the following road gaps

(i) Mokhra to Kalanaur.

(ii)Muradpur Tekna to Kalanaur

(iii) Nidana to Samargopalpur.

(iv) Gorawrtolakhan Majra.

(v)Ajaib to Seman.

(vi) Gugehri to Dorar.

(vii) Meham to Badesra.

(viii) Bhaini Bharou to Sukhpura.

(ix) Bharan to Titri-Ganga Nagar.

(x)Ajaib to Bainsi.

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) मुरादपुर टेकना । सड़क वर्ष 1978– 79 में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

(बी) नहीं, भरन से टिटरी गन्ना नगर तक सड़क छोड़ कर ।

Misuse and Embezzlement Cases of Panchayats

***238. Chaudhri Ram Kishan :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the total number of cases of misuse of Panchayat funds and embezzlement pending at present against the Sarpanches of Gram Panchayats in the State and in particular in district Jind togetherwith the time by which the enquiry against the aforesaid Sarpanches is likely to be completed ?

विकास' एवं पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) : इस प्रकार के राज्य में 308 केस तथा जींद जिले में 22 केस लम्बित हैं और इनकी जांच शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Villages Linked with Roads

***284. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the number of villages which are yet to be linked with roads in the State;

(b) the number of villages Which are yet to be linked with the roads in the Nilokheri Constituency ;

(c) the time by which the facility of roads is likely to be provided in all the remaining villages; and

(d) the time by which the steps are likely be taken to start construction work on the link roads which are lying

incomplete ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : (ए) 3 1– 1– 78 तक 1371

(बी) 3 1– 1– 78 तक 21

(सी) कोई समय निश्चित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रगति धन राशिकी उपलब्धि पर निर्भर करेगी ।

(डी) आवश्यक पग पहले से ही लिए जा रहे है ।

Revision of Pay Scales

***299. Shri Devender Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is considering the question of revision of Pay Scales of Senior Auditors/Assistant Accounts Officers/Accounts Officers on the Punjab pattern and also allowing them selection grade; and

(b) the number of Senior Auditors/Assistant Accounts Officers and Accounts Officers who are working in a Department/ Office/Corporation for the last more than five years alongwith steps being taken to replace them so as to enforce the policy of three years stay at one Station/Office ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : (क) नहीं जी ।

(ख) इससे सम्बन्धित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

स्टेटमैंट

निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षक/सहायक लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी, विभिन्न विभागों और निगमों में 5 वर्ष से ज्यादा कार्य कर रहे हैं :––'' क्रम संख्या

पद	विभाग	निगम
1. वरिष्ठ लेखा परीक्षक		8
2. सहायक लेखाधिकारी.		7
2		
3. लेखाधिकारी		

सरकार की ऐसी कोई नीति नही है, जिससे कि विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे वरिष्ठ लेखा परीक्षक, सहायक लेखाधिकारी तथा लेखाधिकारियों को 3 वर्ष से अधिक समय होने पर स्थनान्तारित किया जाये । परन्तु सरकार कीरू यह नीति है कि निगमों/अटोनॉमस बाडीज में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए अधिकारियों को 3 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाए । केवल विशेष परिस्थितियों में यह प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है । 2 सहायक लेखाधिकारियों को जो

प्रतिनियुक्ति पर हैं, प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Water supplied to Sunder Branch and Mitathal Feeder

***322. Shri Tek Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the quantum in cusecs of water supplied to the Sunder Branch and Mitathal Feeder before digging the Jui Canal togetherwith the quantity of water being supplied at present ?

सिचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : वर्ष 1969–70 में अर्थात जुई नहर के चालू होने से पूर्व सुन्दर सब ब्रांच और मिटाथल फीडरमें पानी के वितरण की माला क्रमशरू 186, 458 क्यूसिक्स दिन और 4 4,665 क्यूसिक्स दिन है । जुई नहर के चालू होने के पश्चात् वर्ष 197 0–7 1 से 197 6–7 7 तक औसतन सप्लाई क्रमशरू 25 1, 921 क्यूसिक्स दिन व 49, 230 क्यूसिक्स दिन है ।

Veterinary Hospitals and Stockman Centres

***335. Shri Des Raj :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the constituency-wise total number of Veterinary Hospitals and Stockman Centres in District Karnal and the amount spent for supplying medicines to each one of them during the years 1975-76, 1976-77 i.e. upto 31st December, 1977 ?

विकास तथा पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) :

(क) अपैक्षित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) वर्ष 197 5– 76 में लगभग 1 2, 000 रुपए की राशि दवाईयों के लिए हर एक पशु चिकित्सकालय तथा डिस्पैसरी पर औसतन व्यय की गई तथा लगभग 3100 रुपए की राशि दवाईयों के लिए प्रत्येक पशुधन केन्द्र पर औसतन व्यय की गई । इसी प्रकार वर्ष 197 6– 77 (3 1– 1 2–77 तक) लगभग 1 2, 000 रुपए की राशि दवाईयों के लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालय तथा पशु डिस्पैसंरी पर औसतन व्यय की गई जबकि लगभग 3, 180 रुपए की राशि दवाईयों के लिए प्रत्येक पशुधन केन्द्र पर औसतन व्यय की गई ।

स्टेटमैंट

(क)

	विधान सभा क्षेत्र	कुल संख्या	पशु केन्द्र की संख्या	
			हस्पताल	डिस्पैसंरी
1	नौल्था	5	1	14
2	समालखा	2	—	16

3	घरौण्डा	3	—	18
4	इन्दरी	2	—	2
5	नीलोखेडी	2	1	10
6	करनाल'	2	—	—
7	जुडला	3	1	12
8	पानीपत	1	—	16
9	असन्ध	2	1	8
		22	4	96

Sprinkler Irrigation Equipment

***328. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the amount earmarked for providing sprinklers irrigation equipment to the farmer, during the current financial year ;

(b) whether it is a fact that sprinklers irrigation equipment of inferior quality are being purchased on higher price; if so, the name of the firm from which it is being purchased togetherwith the action taken by the Govt. so far;

(c) whether the Govt. is considering to appoint a committee to go into the details of red tapism, corruption and favouritism in the purchase of sprinklers irrigation equipment

under the Govt. cash subsidy scheme; and

(d) whether it is a fact that the competent technical Department of Central Govt. has opined that seamless aluminium pipes are superior in quality to welded pipes, if so the reasons for purchasing welded pipes despite the fact that the price of seamless pipes is lower and availability is in abundance ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री(श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हरियाणा स्टेट सिंचाई विभाग द्वारा भाखडा नहर सिस्टम पर तुजरबे के तौर पर 20 स्प्रिकलर सैट लगाने के लिए 30 लाख रुपए की स्कीम मन्जूर हो चुकी है ।

(ख) एजेंसियों द्वारा दी गई मशीनरी को सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित की गई कमेटी से मन्जूर करा कर और इस मशीनरी को मौके पर टैस्ट करने के पश्चात् हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग द्वारा यह मशीनरी न्यूनतम दरों पर खरीदी गई हु ।

(ग) सरकारी नकद उपदान स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा स्प्रिकलर की मशीनरी नही खरीदी गई हैं ।

(घ) स्प्रिकलर सैटों के लिए सोविनहीन तथा सीवन–संघनित दोनों प्रकार के एल्यूमीनियम पाईप खरीदे गए है जो पाईप खरीदे गए हैं वे आई0एस0 आई0 के भारतीय स्टैण्डर्ड विशिष्ट 709 2– 1976 के अनुसार हैं और भारत सरकार के

राष्ट्रीय टैस्ट हा उस द्वारा मन्जूर शुदा है । दोनों प्रकार के पाईपों का कार्य सन्तोषजनक है । सोविनहीन पाईपों के रेट काफी सीमा तक कम हैं ।

Possession of Unlicenced Arms

***347. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Industries be **pleased to** state—

(a) the number of cases registered in regard to the possession of unlicenced arms in the Police Station Kaithal during the months of December, 1977 and January, 1978; togetherwith the number of unlicenced arms taken possession of by the aforesaid police station; and

(b) whether the challans of the persons involved in the cases as referred to in part (a) above have been presented in courts for trial ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) :

	थाना	मास	दर्ज किए गए अभियोग	बिना लाईसैंस हथियार जो पकड़े गए
(अ)	सदर कैथल	दिसम्बर, 77	2	1 बरछा, 1 पिस्तौल व 1 कारतूस

शहर कैथल	दिसम्बर 77	2	2 पिस्तौल व 1 कारतूस
सदर कैथल	जनवरी, 78	3	2 बरछे, 1 पिस्तौल व 5 कारतूस
शहर कैथल	जनवरी, 78	1	1 एक नाली बन्दूक व 5 कारतूस

(ब) भाग अ में अंकित 8 अभियोगों में से 2 अभियोगों के चालान कचहरी में दायर किए गए हैं । शेष 6 अभियोग अनुसन्धानाधीन हैं ।

Taking over of Private Denomination Colleges

***377. Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government is considering to evolve a policy to take over gradually all the private denomination colleges in the State; and

(b) if not then what other steps are under consideration of the Government to ameliorate the deteriorating conditions of these colleges ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) नहीं ।

(बी) विधान सभा के चालू अधिवेशन में एक विधेयक 'दी हरियाणा प्राईवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) विधेयक, 197 8'' कुप्रबन्धित अराजकीय महाविद्यालयों को अस्थाई तौर पर नियन्त्रण में लेने हेतु पेश किया जा रहा है ।

Canteens being run by the Tourism Department in the State

***365. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the total number of canteens being run by Tourism Department in Haryana togetherwith the names of places where the canteens are located ; and

(b) the year in which the canteens as referred to in part (a) were set up and the year-wise annual expenditure incurred on these canteens and the year-wise income accrued therefrom separately ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Tourism Department is not running any canteen at any place in Haryana. All the restaurants/canteens/cafe's located at various tourist complexes in the State are now being run by the Haryana Tourism Corporation which started functioning with effect from 1-9-1974. A statement containing the names of places where such restaurants/canteens/cafe's are located and the date from which they started functioning is laid on the Table of House.

(b) As regards the income and expenditure of the restaurants/ canteens/cafe's run by the Haryana Tourism Corporation; it is submitted that accounts of each complex, which have got various components like motels, camper's huts, shopping arcade, boating, restaurant, canteen etc. are maintained jointly. As such labour and time involved to bifurcate accounts to give this information, will not be commensurate with the benefits to be derived therefrom.

STATEMENT

List of places where Restaurants/Cafe/Canteen are being Run by Haryana Tourism

Corporation

Sr.No.	Name of place	Date of starting of Restaurant	Cafe/Canteen
1.	Badkhal Mayur Grey Falcon	(i) 21-4-69 (ii) 17-8-73	26-9-71
2.	Faridabad	18-1-73	
3.	Surajkund	5-8-69	14-4-73
4.	Hodel	Dec., 1974	Dec, 1974
5.	Sohna	21-8-74	Aug., 73

6.	Dharuhera		1-7-72	
7.	Sultanpur		1-6-72	
8.	Gurgaon		4-11-73	
.	Taoru		3-10-77	
0.	Namaul		26-8-73	
1.	Hissar		22-2-72	
2.	Rohtak	Myna	(i) Nov., 74	
		Tilyar	(ii) March, 77	
3.	And		25-4-72	
4.	Bhiwani		1-5-72	
5.	Panipat		18-1-77	
6.	Sonepat		10-7-74	
7.	Smalkha		May, 1975	
8.	Uchana		1-1-72	Oasis, April, 1973 Cafe, April, 1976
9.	Pipli		28-2-72	
0.	Pinjore		1-11-66	23-10-71

1. Panchkula Dec., 1972

Nazool Land

***401. Captain Mange Rain :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any NAZOOL Land in BIR SUNARWALA JHAJJAR & CHHUCHHAKWASS in Tehsil Jhajjar stands allotted to the persons belonging to Scheduled Castes; and

(b) if reply to part (a) above is in the affirmative, whether the ownership rights in respect of the said land have so far been transferred to the allottees thereof; if not, the reasons therefor and the time by which these are likely to be transferred ?

****INTERIM REPLY**

अर्द्ध सरकारी पत्र क्रमांक 1288र—/—78/6422

प्रीत सिंह, मन्त्री,

राजस्व विभाग, हरियाणा चण्डीगढ ।

दिनांक 2 मार्च, 1978

विषय –तारांकित विधान सभा प्रश्न नं. 401 जो कि श्री कैप्टन मांगे राम एमएलए. द्वारा पूछा गया ।

प्रिय श्री ब्रिगेडियर रण सिंह जी,

कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देवे ।

2. उपरोक्त प्रश्न तारांकित विधान सभा कार्य सूचि दिनाक 3 मार्च, 1978 में शामिल है । यह प्रश्न इस विभाग में 24 फरवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था । इसके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना सचिवालय स्तर पर उपलब्ध नहोने के कारण उपायुक्त रोहतक को उसी दिन सूचना भेजने के लिए वायरलैस सन्देश हारा अनुरोध कर दिया गया था । तत्पश्चात् 28 फरवरी, 1978 को वायरलैस सन्देश भी भेजा मया परन्तु अभी तक सूचना प्रतिक्षित हं ।

3. अत उपरोक्त स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो सप्ताह का समय और देने की कृपा करें

आपका,

हस्ताक्षर

(प्रीत सिंह)

श्री रण सिंह,

अध्यक्ष हरियाणा निधान सभा,

चण्डीगढ ।

Villages Connected with Link Roads

***444. Master Shiv Parshad :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the number of villages connected with link roads in Assembly Constituency of Ambala City during the year 1977-78; and

(b) the number of villages which are proposed to be connected with link roads during the year 1978-79 in the aforesaid constituency ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) शून्य

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नही है ।

Pay Scales of Headmasters/Headmistresses

***419. Shri Bhale Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the pay scales of Headmasters/ Headmistresses of the Government High Schools were previously at par with those of the Junior Lecturers working in Government Colleges ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give pay scale of Rs. 700/1600 to the Headmasters of the Government High Schools in the State, if not the reasons therefor ;

(c) whether the selection grades have been given by the Govern-

ment to the. JBT and C&V teachers' working in Govern-
ment Schools; and

(d) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give Selection Grade to Headmasters/ Headmistresses of Government High Schools in the State ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) हां ।

(बी) नहीं । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने कालिज लैक्चररों के लिए 7 00/1600 रुपए के ग्रेड की सिफारिश की थी । यह सिफारिशें राजकीय उच्च विद्यालयों के मुख्याध्यापकों/मुख्याध्यापिकाओं पर लागू नहीं होती ।

(सी) इस सम्बन्ध में राजकीय उच्च विद्यालयों के मुख्याध्यापकों मुख्याध्यापिकाओं की तरफ से एक प्रार्थना प्राप्त हुई है जिसका निरीक्षण किया जा रहा है ।

Outlets Constructed

***431. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of outlets constructed on the Loharu main canal; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the outlets as referred to in part (a) above; if not, the reasons therefor ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) लोहारू मेन कैनाल पर 64 मोघे है ।

(ख) जी हां ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Industrial Institutes in the State

49 Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open more Industrial Institutes in the State; if so, whether any such Institute will be opened in Hathin Constituency of Mewat Area ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के अधीन नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे विचार किया जा रहा है । हथीन जिला गुडगावां में भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बारे विचार किया जा रहा है । इस बारे विभाग के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी को वहां का सर्वे करने के लिए भेजा जा रहा है । उनकी रिपोर्ट आने पर तथा वित्तीय स्थिति को सामने रखकर निर्णय लिया जा सकेगा कि वहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना उचित है या नही ।

Bridge over Yamuna

50 Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government have taken any decision to construct a bridge over the Yamuna river to connect Gurwari with Jewar in Tehsil Palwal, if so, the time by which the said bridge is likely to be completed?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) नही । फिर भी पलवल तहसील भे यमुना नदी के पर पुल के निर्माण का एक प्रोजैक्ट भारत सरकार के तकनीकी परीक्षण के अधीन है । यह प्रोजैक्ट हरियाणा की ओर चांदहट/'रहीमपुर को, उत्तर प्रदेश कीओर टापल से मिलाने वाली साईट पर आधारित है । यह साईट गुरवारी के नीचे की ओर 2 50 मील की दूरी पर है । भारत

सरकार से तकनीकी मन्जूरी प्राप्त होने पर हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रोजैक्ट को कार्यान्वित करने के बारे निर्णय लिया जाएगा ।

Vends of Liquor

51. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of villages in the State where there are vends to sell country liquor and Indian made foreign liquor shops separately together with the number of such vends of country liquor and Indian made foreign liquor shops in cities, towns and notified areas, separately ;

(b) the cost of production of country liquor and Indian made foreign liquor: together with the price at which each bottle of country liquor and Indian made foreign liquor is sold; separately;

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) :

(ए) (बी)

एक विवरण संलग्न है ।

(सी) व (डी)

विवरण

(ए)

ठेकों की किस्म	ग्रामों की संख्या, जिनमें ठेके हैं ।	ठेकों की संख्या		
		शहर कस्बा	नोटिफाईड एरिया	जोड़
देसी शराब	295	163	60	518
भारत में बनी अंग्रेजी शराब	50	405	49	504

(बी)

	मद्यशाला का नाम	साधारण मसालेदार देसी शराब की 750 मिलि. की एक बोतल का उत्पादन मूल्य जोकि मद्यशालाओं द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1978–77 के रिकार्ड के आधार पर विभाग द्वारा अनुमानित किया गया ।
1	पानीपत सहकारी मद्यशाला, पानीपत	0. 91 रुपए

2 हरियाणा 1.02 रुपए

मद्यशाला

यमुनानगर

विशेष मसालेदार, देशी शराब भारत में बनी विदेशी शराब और बीयर के उत्पादन मूल्य मालूम नहीं । देसी शराब तथा भारत में बनी विदेशी शराब का बिक्री मूल्य स्थान–स्थान पर अलग–अलग हैं ।

(सी)

वर्ष	देसी शराब एल.पी. गैलन में	भारत में बनी अंगेजी शराब एल 0पी 0 गैलन में	बीयरएल0पी0ई गेलन में	वाईनज एल0पी0 गैलन में
1972-73	13,13,704	22,699	—	—
1973-74	23,22,809	1,19,111	—	—
1974-75	13,80,249	1:65,669	4,56,901	—
1975-76	20,41,057	89,889	4,57,086	3,065
1976-77	18,28,154	1,12,603	12,61,268	3,231

(डी) अभी तक 145 ग्राम पंचायतों से शराब की दुकानों को बन्द करने के लिए प्रस्ताव प्राप्तहुए हैं । इनमें से 35 प्रस्ताव 1—4— 1978 से दुकानें बन्द करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं । 25 प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा बाकी 85 प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

Bridge over Gaunchi Drain

52. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge over Gaunchi drain which flows in Palwal and Nuh tehsils between Reendka to Hathin, at Burji No. 84-85 of Sevli village and between Jalalpur, Muafi Garota; if not the reason therefor ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : गौंची मेन ड्रेन की आर0डी 0 1 1 7, 500 पर रीन्डका व हथीन गांव के मध्य एक पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । ग्राम सेवली के लिए आर0 डी0 84,000—— 85,000 की बजाय आर0डी0 82,500 पर पुल बनाने का प्रस्ताव है । ग्राम जलालपुर, मुआफी घरोटा के मध्य आर0 डी0 44,000 पर पुल का निर्माण सरकारद्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और 1978—79 में बना दिया जाएगा ।

Award by Shri Uma Shankar Dikshit

82. Shri Surrender Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the award given by Shri Uma Shankar Dikshit the then Union Home Minister, regardig the boundary dispute between Haryana and Uttar Pradesh ;

(b) whether the award as referred to in part (a) above has been implemented ; and

(c) if not, the steps taken or proposed to be taken by the Government to get the award implemented ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh Rathi)

(a) A copy of the Award is enclosed.

(b) Not yet.

(c) The Haryana Government has since sent its consent to the acceptance of the Award. The matter is now with the Government of India and the Bill has to be introduced in the Parliament before it becomes an Act. Govt. of India has been requested to expedite.

The Haryana Uttar Pradesh Boundary Dispute

The Chief Ministers of Haryana and Uttar Pradesh, at a meeting with me on the 17th May, 1974, have agreed that the boundary dispute between the two States may be arbitrated upon by me and that my award will be accepted by both the parties. It was further agreed at this meeting that for the purposes of the arbitration, joint discussions would be held between the officers to be nominated by the two State Governments and an officer to be nominated by me and that the entire boundary question would be gone into by the officers so nominated and the matter submitted to me

thereafter.

2. Shri K.V.K. Sundaram, Adviser to the Home Ministry, was nominated by me to convene meetings and conduct joint discussions with the officers so nominated by the two State Governments. These discussions have been completed by the Adviser and he has submitted to me his report together with the statements, maps and other documents given by the representatives of the two State Governments.

3. Having given the matter my earnest consideration, I give the following award.

AWARD

I. The boundary between Ambala and Kurukshetra districts of Haryana on the one side and Saharanpur district of Uttar Pradesh on the other, is already a fixed boundary as to the location of which there is no dispute.

II. The boundary between Karnal and Sonepat districts of Haryana on the one side and Saharanpur, Mazaffarnagar and Meerut districts of Uttar Pradesh on the other side has been taken by both the parties to be the fluctuating deep stream of the river Yamuna. Hereafter, this boundary will be fixed at the present deep stream line of the river as verified and determined by the Survey of India during the months of November, 1974, December, 1974 and January, 1975. This has been agreed to by the representatives of both the State Governments and the river survey is being conducted

by the Survey of India with an observer from each side.

III. The boundary between Gurgaon district of Haryana on the one side and Bulandshahr and Aligarh districts of Uttar Pradesh on the other side shall hereafter be fixed at the line specified below :-

(1) The line shall commence from the point where the present deep stream line crosses the north-west boundary of BASANTPUR and proceed along the said boundary up to the point where it crosses the north bank of the river Yamuna as ascertained at the 1971-72 river survey conducted by the Survey of India.

(2) It then proceeds along the said north bank up to the point

where it meets the boundary between BASANTPUR and SALARPUR; thence along the northern and eastern boundaries of SALARPUR, the eastern boundary of ASA-IATPUR, the north-eastern boundary of DADSIA, the northern and north-eastern boundaries of KIRAWLI, the northern boundary of LALPUR, the northern and eastern boundaries of MAHABATPUR, the eastern boundary of MUAZZAMABAD, the eastern and northern boundaries of RAJPUR KALAN including CHAK PUHLERA, the northern and eastern boundaries of SHIKARGAH, the northern and eastern boundaries of AMINPUR, the eastern boundary of CHIRSI, the eastern boundary of AK ABARPUR, the eastern boundary of MOZAMABADMAZRA-SHEIKHPUR, the eastern boundary of MANJHAWLI, the eastern boundary of GARHI BEGAMPUR, the south-eastern boundary of DALELGARH, the eastern boundary

of NANGIA-MAZRA-CHANDPUR, the northern and eastern boundaries of SHAHJAFANPUR, the eastern boundary of LATIFPUR, the eastern boundary of PARASRAMPUR alias DULEHPUR, the eastern boundary of MAKANPUR, the north-eastern boundary of WALIPUR, the western, northern and eastern boundaries of SHEIKHPUR, the northern and the north-eastern boundaries of BEHARAMPUR, and the north-western boundary of NANGLIA up to the point where it meets the present deep stream line.

(3) From this point it proceeds along the presentdeep stream line following the boundary on Uttar Pradesh side of NANGLIA, JHUPPA, BAGHPUR KALAN, BAGHPUR KHURD, SOLRAH, BHOLRA, DOSTPUR, GURWARI and CHANDHAT up to the junction of the old main stream of the river Yamuna and the channel or branch of the river commonly known as the Zair Nala, and thence along the present deep stream line up to the southern boundary of MAHOLI.

Explanation :—In this paragraph—

(a) any reference to the boundary of a village named in subparagraph (1) or (2) shall be construed as a reference to the boundary of that village as ascertained and mapped at the Settlement of Gurgaon district completed in 1943;

(b) the references to the present deep stream line at the end of sub-paragraph (2) and at the beginning of sub-paragraph (3) shall be construed as references to the deep stream line pertaining to the old main stream of the river

Jamuna as verified and determined by the Survey of India in the month of January, 1975.

IV. The boundary between Gurgaon district of Haryana on the one side and Mathura district of Uttar Pradesh on the other is already a fixed boundary in regard to the location of which there is no dispute.

Sd/-

Uma Shankar Dikshit

14-2-1975

Head Works at Tajewala

83. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the details of steps taken by the Government to construct the proposed Head Works at Tajewala ?

सिचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : ताजेवाला के समीप हथीन कुण्ड बेरेज के निर्माण के लिए निम्न पग उठाए गए हैं ।

1. सर्वेक्षण और अन्वेषण पूर्ण हो चुके हैं ।

2. प्रयोजना प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है ।

3. हाईड्रॉलिक माडल का अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र पूने में जारी है तथा जून, 1978 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

4. माडल के अध्ययन के कार्य को अनुसन्धान केन्द्र पूने द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने पर ही यह कार्य हो सकेगा ।

Per Capita Expenditure on Medicines

101. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state the per capita expenditure on medicines durg the years 1967-68 and 1976-77 in the State, separately ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा) : हरियाणा राज्य में दवाईयों पर प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशरू 196 7—68 में 0. 21 रुपए तथा 197 6— 77 में 1. 05 रुपए था ।

New Mandis in the State

102. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of mandis existed in the State of Haryana on 1st April, 1977; and

(b) the total number of new mandis sanctioned from 1st April, 1967 to 1st March, 1976 togetherwith the year-wise breakup and names thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) 127.

(b) 56.

Year	Mandis sanctioned by Market Committees year-wise		Mandis sanctioned by Colonisation Department year-wise.	
	No.	Name of Mandis	No.	Name of Mandis
1969-70	1	Sohna	—	-
1970-71	—	—	5	Bhiwani, Tosham, Pundri, Rajound, Hathin
1971-72	1	Dhand	11	Rewari, Kosli, Jhajjar Gohana,Indri,Radaur, - Naraingarh, Yamuna Nagar, Ambala City Ratiaand Rania.
1972-73	6	Sadhaura, Shajzadpur, Jundla, Balsamand, Farrukanagar and Mud-laud a.	—	—

1973-74	4	Radaur, Jui, Bahal and Naneela	7	Ballabagarh, Rohtak, Beri, Taraori , Samalkha, Ding and Narnaund.
1974-75	2	Bilaspur, Hassanpur	7	Gurgaon, Kunjpura, Assandh, Pabra, Dhassu Kalan, Jhojju Kalan and Kundli
1975-76	4	Kharkhauda, Kalka, Rohtak and Kalanaur	8	Barara,Meham,Ismaila-bad, Babain, Amin, Ferozepur Jhirka, Bara Gura and Kundi.
1976-77	—	—	—	—

Note.—Markets at Radaur and Rohtak which were originally sanctioned by the Colonisation Deptt. in the year 1971-72 and 1973-74 respectively were later on developed by the Haryana Agricultural Marketing Board and as such shown in both sides.

ध्यानाकर्षण सूचना तथा सिंचाई एवं बिजली मंत्री द्वारा वक्तव्य

Mr. Speaker : I have received a notice of a Call Attention Motion concerning the destruction of hundreds of

acres of standing crops in Narwana and Jind Sub Divisions on 2nd March, 1978, from Sarvshri Shamsher Singh and Birinder Singh, M.L.As.

The motion is admitted.

Shri Shamsher Singh may please read his motion.

Shri Shamsher Singh : On the night intervening 1st and 2nd of March, 1978, and on the afternoon of 2nd March, 1978, several villages of Narwana and Jind Sub Divisions, of the District of Jind were lashed by several hail storm resulting in the wholesale destruction of hundreds of acres of standing crops of mustard, gram and wheat. The size of the hails is said to be unprecedented. This has resulted in the total loss of the standing crops depriving hundreds of farmers of their livelihood. Immediate relief operations can mitigate the sufferings due to natural calamity be fallen on the poor farmers. The Government should order special girdawaris to assess the loss caused to each one of the farmers. Total remission of land revenue and water charges should be announced. Government should also grant compensation to the affected farmers as is being done in the event of all natural calamities.

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, मेरे दोस्त की तरफ जो काल अटैशन मोशन आई उसका पता मुझे उनकी जबान से सवा 9 बजे मिला । इसके बारे में अभी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन मेरे दोस्त कह रहैं हैं, इसमें भी काफी सदाकत हो सकती है । मैं इस सदन को विश्वास दिलाता

हूं कि आज ही सम्बन्धित अफसरान को आदेश जारी कर दिए जाएंगे और पूरी तरह जितना भी रिलीफ जमीदारों की हिफाजत के लिए सरकार को मुमकिन होगा, दिया जाएगा ।

श्री शमशेर सिंह : जो वहां डिस्ट्रक्शन हुई है, क्या उसका कम्पनसेशन देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इनक्वायरी के बाद ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने तीन दिन पहले कहा था कि मेरी काल अटैशन मोशन का जवाब देंगे, दो तीन दिन तो बीत चुके हैं, कब तक जवाब देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब ने उसके लिए 6 तारीख निश्चित की है, उस दिन जवाब दे देंगे ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, एक और भी काल अटैशन मोशन थी, कपास के बारे में उसका जवाब कब देंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : उसका भी 6 तारीख को जवाब दे दिया जाएगा ।

राज्यपाल का सन्देश

Mr. Speaker : I have received a message from the Governor which reads as follows—

I beg to acknowledge receipt with. thanks of your

demi-official letter No. 5150 dated the 1st March, 1978, forwarding a copy of the Motion of Thanks passed by the Haryana Vidhan Sabha at its meeting held on the 1st March, 1978. Please convey my thanks an i appreciation for their Kind thought

in accepting the Motion.". (Thumping)

विधायकों के लिऐ अभिविन्यास प्रशिक्षण कोर्स सम्बंधी अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Hon. Members, I am glad to inform you that an important training course for M.L.As. of Northern Zone is being inaugurated by the Prime Minister on 19th March. 1978. During this ten days' course experienced and renowned parliamentarians and eminent personalities will lecture and hold discussions for the benefit of the new legislators. The valedictory address of the course will be delivered by the Speaker Lok Sabha on 31st March. A copy of the programme of the course has been placed in the Library, Lobby and on the Notice Board. I have already received some names for this course. The remaining members who are interested in this course are welcome to give their names by 6th or 7th March, 1978.

वर्ष 1978 – 79 के लिए बजट पेश करना

वित मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : ऐ श्री मान् अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 197 8– 79 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

वर्तमान सरकार ने जून । 1 977 में कार्यभार सम्भाला था । आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकार जनता पार्टी द्वार जनता के सा मने रखे गए लक्ष्यो को पूर करने सम्बन्धी नीतियां तथा कार्य क्रम अपना ने के लिए वचनबद्ध हैं । अतः हमारे आर्थिक कार्य कम का ध्ये य गरीब दूर करने के साथ–साथ कु षि को प्राथमिकता तथा रोजगार को बढ़ावा दे ने वाली विकास स्कीमो पर जोर दे ना । तथा अनिवार्य वस्तुओं की कीमत ओं को स्थिर रखने के लिए पग उठाना है ताकि उनकी कीमतें आम आदमी । की खरीदने की–क्षमता से बाहर न चली जा एं । आगामी वर्ष के बजट में प्रस्त वित विकास–व्यय के द्वरा इन सभी उद्देश्यों को पूर करने का प्रयास किया गया है ।

आर्थिक स्थिति

इस सरकार के कार्यभार सामने के तत्काल बाद इसे विनाशकारी बाढ़ों द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का सा मना करना पडा । बाढ का प्रकोप तथा लपेट इतनी अधिक थी जिसका पहले उदाहरण नही मिलता । और इसने राज्य के कुरुक्षेत्र के एक तिहाई भाग से अधिक की अर्थ–व्यवस्था को लगभगपूर्णतया नष्ट भ्रष्टकर दिया । लगभग सात लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खाद्यान्नों, कपास, सब्जियों, तथा गन्ने की खरीफ की फसले पूर्णत नष्टहो गई अथवा उन्हें बहुत ज्यादा नुक्सान पहुचा ।. चावल की फसल को छोडकर, खरीफ उत्पादन 1976 के 15.96 लाख टन की तुलना में घटकर चालू वित्त वर्ष में 14. 36 लाख टन रह गया ।त

गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा महेन्द्रगढ़ के जिलों में विशेष रूप से, लगभग 1800 गांवों में रहने वाली 18 लाख की आबादी को बाढ़ का प्रकोप सहन करना पड़ा । फसलों, पशुओं 'तथा सम्पत्ति को हुए नुक्सान का अनुमान 100 करोड़ रुपए लगाया गया है । इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा । मैं बाढ़ नियन्त्रण तथा राहत कार्यों का उल्लेख थोड़ा बाद में करुंगा । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि खेतों कों बुवाई योग्य बनाने के लिए उनमें से पानी निकालने का कार्य आपातिक तौर पर 1 50 करोड रुपए की लागत से किया गया । किसानों को, विशेषत बाढग्रस्त क्षेत्रों में, कृषि सामग्री के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि के कर्जे दिए गए । सरकार ने सहायता के विचार से छोटे किसानों को बीजों तथा रासायनिक खादों की खरीद के लिए 1. 27 करोड़ रुपए की राशि की आर्थिक सहायता दी । बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रो में जरूरतमन्द किसानों के लिए 30 लाख रुपए के तकावी कर्जे मन्जूर किए गए, ताकि वे अपने खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टरों के डीजल का खर्च तथा किराया–भाडा दे सकें । हमें आशा है कि इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हमारे किसान रबी की उत्तम फसल ले पाएंगे ।

जैसा कि आदरणीय सदस्यों को विदित है, देश में आपात स्थिति समाप्त होने से फैक्टिरियों के कामगारों को अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाने का अधिकार पुनरू प्राप्त हो गया है ।. कठोर दमनकाल की समाप्ति पर कामगारों द्वारा अपनी

मांगें पूरी करवाने के लिए प्रदर्शनों तथा हड़तालो का सहारा लिया गया । अब तक 1977 के दौरान 103 हड़ताले तथा तालाबन्दियां हुई हैं जबकि इससे पिछले वर्ष केवल 6 हड़तालें तथा ताला– बन्दियां हुई थीं । परन्तु अब राज्य सरकार कामगारों की जायज तथा वास्तविक मांगों के प्रति उदासीन नही है । सरकार ने इसमें गहरी रुचि ली है तथा राज्य की समझौता मशीनरी को सक्रिय बनाया गया है । परिणामतरू, आदरणीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि लगभग सभी मामलों में कामगारों तथा प्रबन्धकों के बीच मन्त्रीोदों को मैत्रीपूर्ण बातचीत से निपटाया गया तथा समझौतों के परिणामस्वरूप कामगारों के वेतनों, मकान किराया, सवारी भत्ते, आदि में प्राय तदर्थ वृद्धि हुई । बहुत से मामलों में जो कामगार नि– लम्बित कर दिए गए थे या जिन्हें सेवा से अलग कर दिया गया था, नन्हें भी बहाल किया गया । उद्योगों के विकास में सहायक शान्तिपूर्ण तथा अनुशासनात्मक वातावरण दोबारा पैदा किया गया है तथा इसे बनाये रखा जाएगा ।

लघु यूनिटों की संख्या वर्ष 197 6– 77 में 1 9, 252 से बढ़कर दिसम्बर, 1977 की समाप्ति तक 2 0, 610 हो गई है । चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 300 और यूनिटों के पंजीकृत होनेकी सम्भावना है । बडे तथा मध्यम दर्जे के क्षेत्र में दिसम्बर, 1977 के अन्त 14 औद्योगिक लाईसेंस. तथा 10 आशय पत्र जारी किए गए । इससे इनकी कुल संख्या क्रमशः 320 तथा 829 हो गई । राज्य

सरकारद्वारा अपनी नई औद्योगिक नीति का पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण औद्योगिकरण की स्कीम चालू की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों से सम्बद्ध 2 से 4 शिक्षित ग्रामीण युवकों के समूह को ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन यूनिट स्थापित करने केलिए वित्त, कच्चे माल, विपणन तथा तकनीकी ज्ञान की इक– मुश्त सहायता दी जाती है । इस स्कीम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान 10 यूनिट प्रति किला के हिसाब से 1 10 औद्योगिक यूनिट तथा वर्ष 197 8–79 में 330 अन्य यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे चालू वर्ष में 1, 000 शिक्षित ग्रामीण युवकों तथा वर्ष 1978–79 में 2, 500 शिक्षित ग्रामीण युवकों के लिए सीधे रोजगार के अवसर जुटाए जाएंगे । आशा की जाती है कि यह मार्गदर्शक स्कीम ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध होगी । माननीय सदस्य इस बात से अवगत ही है कि आपार स्थिति एवं इसकी अत्याधिक उपलब्धियों का दावा करने के बावजूद अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते रहे । जनता सरकार इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता दे रही है और उत्पादन में वृद्धि करके तथा जन–वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करके इस पर नियन्वण करने का प्रयास कर रही है । केन्द्रीय सरकार की मुद्रा तथा राजकोषीय नीतियां मूल्य एवं मजदूरी पर निंस्संदेह महत्वपूर्ण भाव डालती है । इस सम्बन्ध में नई केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियां सफल रही हैं । थोक मूल्यों का अखिल भारतीय

सूचकांक (आधार 1 970–71), जो बढ़कर जुलाई, 1977 में 1887 तक पहंच गया था, नवम्बर, 1977 में कम होकर 183. 9 हो गया । आशा है कि आगामी महीनों में कीमतें लगातार कम होती रहेगी ।

लेखे 1976–77

महालेखापाल, हरियाणा द्वारा संकलित किए गए लेखे के अनुसार 197 6– 77 का वर्ष 1768 करोड़ रुपए के घाटे के साथ समाप्त हुआ । परन्तु, वास्तव में 197 6– 77 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया अर्थोपाय ऋणों को शामिल करके वर्ष 197 6– 77 का घाटा 18. 49 करोड़ रुपए हो जाता है । इस प्रकार, वास्तविक लेन–देन के अनुसार वर्ष के इति– शेष में संशोधित अनुमानों की तुलना में 12 91 करोड़ रुपए की कमी रही । यह कमी मुख्यतरू राज्य सरकार की राजस्व आय में कमी के कारण हुई । नगरीय सम्पदाओं के बेहतर विकास के लिए राज्य सरकार ने 197 6– 77 में ''हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण'' की स्थापना की थी, जोकि नगरीय सम्पदा विभाग की लेनदारियों तथा देनदारियों का उत्तराधिकारी बना । इसलिए, प्लाटों की 'बिक्री' से हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण को 2. 70 करोड़ रुपए की आय हुई । बिजली बोड' अपनी वित्तीय कठिनाईयों के कारण राज्य सरकार को 1. 40 करोड़ रुपए का ब्याज न– दे सका । राज्य के कुछ भागों में सूखे की अवस्था तथा अम्बाला और गुडगांव जिलों में ओले से रबी की खड़ी फसलों को हुई हानि के

कारण किसानों से तकावी कर्जों की अनुमानित वसूली में 1 81 करोड़ रुपए की कमी हुई । निर्धारित परियोजनाओं पर हुए खर्च में कमी के कारण भारत सरकार से भी 3. 00 करोड़ रुपए की कम केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई । लगभग 4. 00 करोड़ रुपए की शेष कमी विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत हुई और यह आंशिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को जोर–जबरदस्ती सें–लागू करने के कारण पैदा हुए वातावरण के कारण हुई ।

संशोधित अनुमान 1977– 78

जैसा कि मैंने पहले बताया है, 197 7– 78 का वर्ष 1 8. 49 रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ । राज्य विधान मण्डल द्वारा वर्ष 1977–78 का बजट पारित कर दिए जाने के बाद पिछली सरकारद्वारा घोषित की गई कुछ राहतों तथा रियायतों केकारण स्थिति और खराब हो गई । वर्तमान सरकार के कार्यभार सम्भालने के समय तक राज्य का रिजर्व बैक आफ इण्डिया से ओवर ड्राफ्ट 37 करोड रुपए की सीमा तक पहुंच गया था । जुलाई से सितम्बर, 1977 की अवधि मे राज्य में आई भयंकर बाढ़ों से स्थिति और भी गम्भीर हो गई । अतः हमने राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति स्थिर करने की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया ।

चालू वर्ष के बजट अनुमानों के संशोधन तथा वर्ष 197 8– 79 के बजट अनुमानों के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली स्थिति नीचे दी गई है :

	बजट अनुमान 1977–78	संशोधित अनुमान 1977–78	बजट अनुमान 1977–79
		(रुपए करोड़ों में)	
1 अथ शेष (लेखों के अनुसार)	-5.58	--17.68	+7.91
2 राजस्व लेखे :			
राजस्व प्राप्तियां	294.05	298.02	331.92
राजस्व खर्च	238.91	243.32	278.20
अधिशेष (+)	+55.14	+54.70	+53.72
3 पूजी लेखा (निवल)	63.95	60.48	94.27
4 लोक ऋण			
लिया गया उधार	134.98	166.27	166-25
लौटाया गया उधार	126.65	124.69	144.28
निवल	+8.33	+41.58	+21.97
5 उधार/पेशगियां पेशगिया	41.15	39.05	51.42

	वसूलियां	8.38	6.59	11.08
	निवल	+32.77	-32.46	-40.34
6	अन्तर्राज्यीय निपटान	--	-1.73	-1.36
7	सामान्य भविष्य निधि अंशदान (निवल)	+8.88	+7.40	+8.15
8	जमा/पेशगियां (निवल)	+12.85	+16.58	+17.33
	निवल परिणाम	-- 17.10	+7.91	-26.89

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति 25. 01 करोड़ रुपए तक सुधरने की सम्भावना है । वर्ष 1977–78 के बजट अनुमान में उपबन्धित आयोजनागत खर्च से 20. 84 करोड़ रुपए का अधिक आयोजना– गत खर्च करने के बावजूद वित्तीय स्थिति में यह सुधार हुआ है । इस बात को देखतेहुए यह सुधार और भी उल्लेखनीय–हैकि 197 7– 78 का वित्त वर्ष लेखों के अनुसार 17. 68 करोड़ रुपए के घाटे से आरम्भ हुआ था । हम वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों केविकास इतर खर्च पर पूर्ण नियन्त्रण रख कर, बिक्री कर से अधिक वसूलियां प्राप्त कर, अतिरिक्त साधन जुटा कर और राज्य में आई भारी बाढ़ से पैदा हुई असामान्य स्थिति का सामना करने कें–लिए भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके वित्तीय स्थिति में यह सुधार लाने में समर्थ हुए हैं ।

बाढ के कारण हुई हानि के बावजूद राज्य की आय में, विशेषतरू बिक्री कर, यात्री तथा माल कर, बिजली शुल्क तथा मनोरजन कर से लगातार वृद्धि होती रही, जो कि इस बात की परिचायक है कि आय, पूर्ति्त तथा उपभोग के क्षेत्र में कोई विशेष हानि नहीं हुई । सरकार राज्य की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृत सकल्प है ।

बजट अनुमान 1978– 79

अब मैं सदन के समक्ष वर्ष 19 78– 79 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं । अच्छी आय होने के बावजूद वर्ष 197 8– 79 के बजट अनुमानों में वर्ष के अन्त में 26. 89 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । यह घाटा मुख्यत वर्ष 19 78– 79 के लिए उपबन्धित लगभग 82 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास खर्च के परिणामस्वरूप है जो चालू वर्ष के योजना खर्च से 42 प्रतिशत अधिक है । हमने अपने विकास कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान, 197 8– 79 में भारत सरकार से सामान्य केन्द्रीय सहायता कल्पित की है । जब हम अपनी उपलब्धियों के सन्दर्भ में वर्ष के दौरान उनके साथ अपने साधनों की अपेक्षा के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करेंगे, तो यह सहायता अवश्य बढ़ जाएगी । तथापि, अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों के साथ–साथ विभागों के आयोजना भिन्न विकास खर्च पर अधिक नियन्त्रण रखने का विचार है, ताकि बजट में घाटे को और कम करके उचित सीमा में लाया जा सके ।

वार्षिक योजना 1978– 79

योजना आयोग द्वारा वर्ष 197 8– 79 के लिए 210 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई है । वर्ष 197 7– 78 के योजना खर्च में विकास खर्च की 42 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्षों की वार्षिक योजनाओं की वृद्धियों की तुलना में सबसे अधिक है । सरकार का यह निष्ठापूर्वक निश्चय है कि राज्य में विकास कार्यो को तेज किया जाए ताकि पहले की अपेक्षा लोगों की आर्थिक स्थिति में और तेजी से सुधार किया जा सके । राज्य के लोगों से किए गए वायदों के अनुसार यह आशा की जाती है कि सभी सरकारी एजेंसियां लगन से कार्य करेंगी तथा लोगों के प्रतिनिधियों, गैर–सरकारी एजेंसियों तथा स्वयं सामान्य जनता का सहयोग प्राप्त होगा । खर्च का प्रमुख भाग, 144. 09 करोड़ रुपए अर्थात् कुल योजना का 68 प्रतिशत भाग केवल सिंचाई तथा बिजली परही खर्च करने का प्रस्ताव है । इसके अन्तर्गत 27 20 करोड़ रुपए महत्वपूर्ण सतलुज–यमुना लिंक परियोजना पर खर्च किए जाएंगे जिससे हरियाणा के हिस्से का रावी–व्यास का जल राज्य के सूखे क्षेत्रों में ले जाया जाएगा । 12. 50 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना पर, 10 करोड़ रुपए फरीदाबाद थर्मल परि– योजना (यूनिट ।।।) पर तथा 15. 39 करोड़ रुपए पानीपत थर्मल परियोजना चरण 1 कथा ।। पर खर्च किये जाएंगे । कृषि तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए आगामी वर्ष की स्वीकृत योजना में 22 68 करोड़ रुपए रखे गए हैं । सिंचाई तथा कृषि

को दी गई प्राथमिकता से जनता सरकार की नीति का स्पष्ट रूप से पता चलता है ।

यातायात तथा संचार व्यवस्था के लिए 14. 78 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया हे, जिससे सड्कों तथा यातायात सेवाओं के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाएगा । आगामी वर्ष मे सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं केलिए स्वीकृत परिव्यय 24. 24 करोड रुपए है । इससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं और ग्रामीण तथा शहरी जल सप्लाई की स्कीमों में वृद्धि की जाएगी ।

विस्तृत विभागीय योजना आवंटन का वर्णन करने के पश्चात् अब मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख आगामी वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख विकास विभागों में कार्यान्वित किए जाने वाले विकासात्मक क्रियाकलापों की मुख्य रूपरेखा प्रस्तुत करता हूं ।

सिंचाई

राज्य में लम्बे अरसे से सिंचाई के लिए पानी की कमी चली आ रही है । जल संरक्षण तथा नए क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्कीमों को परम अग्रता दी गई है । बडी तथा दर्मियानी सिंचाई स्कीमों पर खर्च वर्ष 1 97 7— 78 में 52. 84 करोड़ रुपए से बढ़ा कर वर्ष 1978—79 में 58. 51 करोड रुपए कर दिया गया है । लघु सिंचाई स्कीमों पर खर्च वर्ष 197 7— 78 में 0. 58 करोड़ रुपए से बढ़ा कर वर्ष 1 97 8— 79 में एक करोड़

रुपए कर दिया गया है । रावी–व्यास के फालतू जल में से हरियाणा का हिस्सा लाने के लिए सतलुज– यमुना लिंक कार्य का हरियाणा में स्थित भाग वर्ष 1 97 8– 79 में पूरा हो जाएगा । हमें आशा है कि पंजाब में भी सतलुज यमुना लिक पर कार्य जल्दी ही शुरु हो जाएगा । हमने सतलुज–यमुना लिंक कार्य पर पंजाब सरकार द्वारा खर्च किए जानेके लिए वर्ष 197 8– 79 के बजट प्रस्ताव में 1 9 करोड़ रुपए की राशि का उपबन्ध किया है ।

वर्तमान सिंचाई प्रणाली की क्षमता में सुधार लाने के लिये जलमार्गों के आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें वर्तमान नहरों को पक्का करने का कार्य शामिल है, परम अग्रता दी गई है । सिंचाई जलमार्गों के आधुनिकीकरण की परियोजना के लिये विश्व बैक की सहायता प्राप्त करने के संबंध में बातचीत हो रही है । विश्व बैक की सहायता से आगमीऐं. 4 वर्षों की अवधि में इस कार्य पर 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी । वर्ष 1977–7 8 के दौरान इस कार्य पर 1. 50 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले में वर्ष 1978– 79 में 10 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है ।

वर्तमान सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले 0ंचे तथा 0ंचे–नीचे क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिये प्रायोगिक रुप से नहर प्रणाली पर एक सौ छिड़काव सैट लगाये जा रहे हैं । राज्य के सूखा–सम्भावी क्षेत्रों में चल रही उठान सिंचाई स्कीमों ने संतोष–जनक प्रगति की है । लोहारू तथा सिवानी उठान सिंचाई स्कीम

को मार्च, 19 ओं 9 तक पूरा करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1978–79 के दौरान जवाहरलाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम के लिये 12. 50 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

वर्ष 1977 के वर्षाकाल में राज्य को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा । इन बाढ़ों के बाद राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक बाढ़ सलाहकार समिति बनाई गई है । इस समिति ने 138 करोड़ रुपये व्यय वाली व्यापक बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास महायोजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की है । केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय दल द्वारा बाढ़ नियन्त्रण स्कीम अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् वर्ष 1 97 7–78 के दौरान 1 1. 00 करोड़ रुपये (इस राशि में सड्कों के लिए 3 करोड़ रुपये भी शामिल हैं) की पेशगी आयोजना सहायता मंजूर कर दी है । गत वर्षों में बाढ़ नियंवण एवं जल निकास स्कीमों पर लगभग 2 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले में चालू वित्त

वर्ष में 1 0. 45 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा । वर्ष 197 8– 79 में बाढ़ नियवण तथा जल–निकास स्कीमों पर खर्च और बढा कर 18. 82 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा । महत्वपूर्ण बाढ़ नियन्वण तथा जल निकास कार्यो से किला रोहतक में झज्जर, बहादुरगढ़, चुडानी, भूपनिया तथा जिला गुड़गांव में मेवात के क्षेत्रो को बाढ. से विशेष राहत मिलेगी । इन स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उजीना मोड़ नाले का निर्माण, साहिबी नदी पर मसानी बांध का निर्माण, गांवों

के इर्द–गिर्द रिंग बांधों का निर्माण, नाले बनाना तथा नालों को गहरा करना, जिसमें नजफगढ नाला भी सम्मिलित है, जिस की क्षमता 3, 000 क्यूसेक से बढ़ा कर 10, 000 क्यूसिक करने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाना है, तथा इक्का–दुक्का गड्ढों को मुख्य जल निकास प्रणाली से जोड़ने कें– लिए योजक नालों. के. निर्माण का – कार्य । बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास स्कीमों की गति आगामी 5 वर्ष तक तेज रखने का प्रस्ताव है ताकि राज्य को बाढों से पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके । बिजली

वर्ष 1978– 79 की वार्षिक योजना में बिजली उत्पादन स्कीमों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इनके लिये 37.14 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है । इसमें से 30. 07 करोड़ रुपये की राशि व्यास यूनिट–। व्यास यूनिट–।।, फरीदा– बाद में 6 0– 80 मैगावाट के तीन सैट, पानीपत में 110–1 10 मैगावाट के दो सैट तथा पश्चिमी यमुना नहर पन–बिजली आदि चालू उत्पादन स्कीमों के लिये निर्दिष्ट की गई है । 7 07 करोड़ रुपये की शेष राशि वर्ष 197 8–7 9 के दौरान शुरू की जाने वाली नई बिजली उत्पादन स्कीमों, जैसे पानीपत चरण–।। में 1 1 0– 1 10 मैगावाट के दो सैट, देहर विस्तार, पौंग विस्तार तथा अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में साझेदारी के लिये है । 21.09 करोड़ रुपये व्यास पारेषण लाइनों, बोर्ड की अपनी पारेषण लाइनों के निर्माण पर हानि कम करने और उप–पारेषण और वितरण के लिये प्रयोग में लाये जायेगे। 10.50 करोड़ रुपये स्थानीय वितरण प्रणाली तथा कृ

षि– प्रयोजनों के लिये नलकूपों' को बिजली देने पर खर्च किए जायेंगे । चालू वर्ष के दौरान 1 2, 000 नलकूपों को बिजली दे दी जायेगी तथा आगामी वर्ष के लिये 1 8, 000 नलकूपों को बिजली दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त 1. 00 करोड़ रुपये नया मीटर रिले परीक्षण प्रयोगशाला ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने के लिये वर्कशॉप और स्ट्रक्चरल वर्कशॉप आदि स्थापित करने पर खर्च किये जायेंगे ।

चालू वर्ष के दौरान देहर बिजली घर के 16 5– 165 मैगावाट के दो जनित सैट चालू किये गये हैं और आगामी वित्त वर्ष के दौरान दो और जीनव सैट चालू किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त वर्ष 1978 में पौंग बांध पर 60– 60 मैगावाट के चार जनित्र हैट चालू किये जायेगे । देहर तथा पौंग बांध के सैट चालू हो जाने के बाद भाखडा तथा व्यास परियोजनाओं में हाइड्रो स्थापित क्षमता में हरियाणा का हिस्सा 403 मैगावाट से बढ़कर 85 2 मैगावाट हो जायेगा ।

पानीपत तापीय संयन्त्र के चालू हो जाने पर बोर्ड की तापीय संयन्त्र की अपनी स्थापित क्षमता 204 मैगावाट से बढकर 507 मैगावाट हो जायेगी । बिजली की कमी को पूरा करने के लिये बोर्ड बदरपुर, आर0ए0पी0पी0 जैसे केन्द्रीय– अनिल स्टेशनों से बिजली खरीदेगा । बोर्ड अन्य राज्यों से भी बिजली की खरीद– की संभावना का पता लगा रहा है । सरकार हुस बात के लिए प्रयत्नशील है कि कृषि तथा उद्योग के लिये पर्याप्त बिजली

उपलबध हो ताकि बिजली की कमी के कारण उत्पादन को हानि न पहुंचे ।

विभिन्न पन–बिजली परियोजनाओं तथा बोर्ड की अपनी बिजली उत्पादन– स्कीमों से अधिक बिजली उपलब्ध होने पर वर्ष 1 97 7– 78 दौरान बोर्ड का राजस्व 47. 88 करोड़ रुपये से बढ़कर 1 97 8– 79 के दौरान 63 46 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है ।

कृषि उत्पादन

वर्ष 197 7– 78 के लिये खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 50. 30 लाख टन निर्धारित किया गया है । खरीफ के मौसम के दौरान अत्यधिक वर्षा होने के कारण मकई, बाजरा तथा ज्वार की खड़ी फसलों को काफी क्षति पहुंची । सरकार ने बाढ़– ग्रस्त क्षेत्रों में रियायती दरों पर चारा तथा प्रमाणित बीज वितरित करके लोगों की सहायता की । मकई, बाजरा तथा ज्वार की फसलों को वर्षा तथा बाढ़ों के कारण हुई भारी क्षति के बावजूद इन फसलों का कुल उत्पादन 1 4 38 लाख टन हुआ ह चावल का उत्पादन विशेष रूप से अधिक हुआ है । यह उत्पादन 9. 72 लाख टन तक पहुच गया जबकि वर्ष 1 97 6– 77 के दौरान अधिकतम उपलब्धि 8. 17 लाख टन थी । माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि चावल के प्रति हैक्टेयर उत्पादन के लिये हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है ।

खरीफ मौसम में चावल की अधिक उत्पादन वाली किस्मों के 1 1, 400 क्विंटल प्रमाणित बीज 1 50 रुपये प्रति क्विटल की रियायती दर पर दिए गए । चावल के प्रमाणित बीजों पर 50 रुपये प्रति क्विटल रियायत दी गई । 3, 857 क्विटल. संकर बाजरे का बीज भी दिया गया ।

चालू रबी मौसम के दौरान राज्य मे गेहूं की अधिक उत्पादन वाली किस्मों के 4 8, 250 क्विटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए । गेहूं के बीजों पर 50 रुपय प्रति क्विटल की रियायत दी गई थी । 1 4, 260 क्विंटल चने क्एरू बीज भी 1 00 रुपये प्रति क्विंटल की रियायत देने के पश्चात् 200 रुपये प्रति क्विटल की रियायती दर पर वितरित किए गए थे । चने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 9 4, 500 राईजोबियम कल्चर भी रियायती दर पर वितरित किया गया ।

वर्ष 1977– 78 के दौरान रासायनिक खाद के लिए 1 27 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और परिणामस्वरूप– 197 6–7 7 के रबी मौसम में रासायनिक खाद की 98, 806 टन खपत के मुकाबले में चालू रबी मौसम में लगभग 1 33 लाख टन रासायनिक खाद की खपत हुई जिससे लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता हैरू.। चालू वर्ष में 1 लाख 85 हजार टन रासायनिक खाद की खपत के मुकाबले में अगले वर्ष के लिये 2 लाख 10 हजार टन रासायनिक खाद की खपत का लक्ष्य रखा गया है । रासायनिक खाद की बिक्री को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त

राज्य सरकार ने प्रभावी वनस्पति रक्षा उपाय भी किए हैं । गत वर्ष के दौरान कपास तथा तिलहन के अन्तर्गत आने वाले क्रमश 1. 04 लाख हैक्टेयर और 1 6, 237 हैक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले चालू वर्ष में 1 39 लाख हैक्टेयर तथा 2 0, 000 हैक्टेयर क्षेत्र पर हवाई छिड़काव किया गया ।

वर्ष 197 8– 79 के लिए 55 05 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । मुख्यत कपास, तिलहन तथा दालों के उत्पादन पर जोर दिया गया है ।

हरियाणा में कृषि–उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए मुख्य उपायों में उथले नलकूपों द्वारा भू–गत जल स्रोतों का संतुलित विकास भी शामिल है । अनुमान है कि मार्च, 1978 तक उथले नलकूपों तथा पम्पिग सैटों की संख्या 2 27 लाख हो जाएगी और वर्ष 197 8– 79 के दौरान यह संख्या बढकर 2 40 लाख हो जाएगी । जुलाई,1978 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के दौरान 2 0, 000 उथले नलकूप तथा 1, 800 पैंम्पिग सैट लगाए जाएंगे । इन स्कीमों पर कुल 24 करोड़ रुपए खर्च होंगै । वर्ष 1978– 79 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 6,000 उथले नलकूप तथा 600 पम्पिग सैट लगाए जाएंगे । भूमि तथा जल–प्रबन्ध उपायों के लिए वर्ष 1977–78 के दौरान 26900 हैक्टेयर सम्भावित उपलब्धि के मुकाबले में वर्ष 1978–7 9 के लिए 44700 हैक्टेयर का लक्ष्य निश्चित किया गया है,

हरियाणा राज्य भूमि विकास तथा सुधार निगम द्वारा वर्ष 197 7– 78 के दौरान 11,004 एकड़ भूमि का सुधार करने और 6, 403 एकड़, क्षेत्र को समतल बनाने की सम्भावना है छोटे किसानो को 75 प्रतिशत् तथा अन्य किसानो को 50 प्रतिशत की दर से जिप्सम पर आर्थिक सहायता दी रही है कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम ने करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और जींद जिलों के लिए 5.55 करोड रुपये की लागत पर 120000 हैक्टयर भूमि के सुधार के लिए एक नयी स्कीम स्वीकृत की है ।

कृषि विस्तार की एक नयी प्रणाली, जिसे प्राय बैनूर प्रणाली के नाम से जाना जाता है, को इस राज्य में अपनाने का प्रस्ताव है । गांव स्तरीय कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं की कुशलता के सुधार के लिये तथा उन्हें परिवहन और अन्य सुविधायें देने के लिये 15 करोड़ रुपये की लागत की एक व्यापक परियोजना विश्व बैक को प्रस्तुत की जा चुकी है ।

पशुपालन

हरियाणा राज्य मुर्राह भैसों' तथा 'हरियाणा' नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें पशु विकास की पर्याप्त सम्भावना है । संकरण तथा कृत्रिम वीर्य– सेचन द्वारा देशीय पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाये गयै हैं । करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, भिवानी तथा सिरसा जिलों में सघन पशु विकास परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं ।

जगाधरी में जरसी संकरण केन्द्र चलाया जा रहा है । राज्य को सघन पशु विकास परियोजनाओं में संकरण को प्रोत्साहन देने हेतु डेनमार्क सरकार के सहयोग से गुड़गांव में प्रशीतन वीर्य बैक भी स्थापित किया गया है ।

विभिन्न पशु–विकास कार्यक्रमों के लिए 197 7–7 8 में 87 लाख रुपये के आवंटन के मुकाबले में वर्ष 197 8– 79 के दौरान 124 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । भारत–आस्ट्रेलियाई पशु प्रजनन परियोजना, हिसार के लिए भी पर्याप्त धन का उपबन्ध किया गया है । अम्बाला, जीद, कुरुक्षेत्र तया भिवानी की चार सघन पशु विकास परियोजनाओं का विस्तार कर दिया जाएगा ताकि 6 0, 000 और पशुओं को इनके अन्तर्गत लाया जा सके । 197 8–7 9 के दौरान प्रत्येक परियोजना के साथ एक प्रादेशिक कृत्रिम वीर्य केन्द्र तथा 1 5 पशुपालन केन्द्र लगाए जाएंगे । भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 197 8– 79 के दौरान हिसार जिले की फतेहाबाद तथा टोहाना तहसीलों में और जिला सिरसा की डबवाली तहसील में तीन नई सघन पशु विकास परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी ।

मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेडपालन तथा 0न के विकास और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं । छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि–श्रमिकों द्वारा प्रतिवर्ष 8, 000 चूजे पालने के लिए सरकारी मुर्गी–पालन फार्म, अम्बाला

को आधुनिक बनाया गया है । 1978–79 के दौरान बायलरों के लिए सघन मुर्गीपालन परियोजना शुरू की जाएगी और इसके साथ एक मुर्गी विपणन संघ भी बनाया जाएगा और मुर्गी फार्मों को लाइसैंस दिये जाएंगे । सुअरों की नस्ल सुधारने के लिए संकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के निमित्त उत्तम नस्ल के सुअर केन्द्र स्थापित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

राज्य में भेड़ तथा 0न विकास के लिए भी पर्याप्त गुंजाइश है । संयुक्त राड विकास कार्यक्रम की सहायता से लोहारू (जिला भिवानी) में एक 0न कोटीकरण एवं विपणन केन्द्र स्थापित किया जा चुका है । यह केन्द्र भेु पालकों से उचित बाजार दर पर कच्ची 0न सीधे ही खरीद लेता है जिससे कि बिचौलिया लाभ नहीं उठा पाता वर्ष 197 8– 79 के दौरान उनकी खरीद के लिए 20 लाख रुपये का उप– बन्ध किया गया है ।

छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सामाजिक– आर्थिक –स्थिति को सुधारने के लिए संकर बछडापालन, मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा भेडेपालन के लिए केन्द्रीय परियोजना चालू की जा चुकी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर बछड़ो के लिए सन्तुलित चारा दिये जाने के अतिरिक्त मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा भेडपालन यूनिटों को छोटे किसानों की स्थिति में पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत तथा सीमान्त और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में 33. 33 प्रतिशत तक आर्थिक

सहायता भी दी जाती है । वर्ष 197 8– 79 में यह कार्यक्रम और व्यापक बना दिया जाएगा ।

राज्य में पशुओं की बीमारियों को प्रभावशाली ढंग से रोकने तथा पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 180 पशु–अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र तथा 128 औषधालय ''रोगी पशुओ की चिकित्सा–देखभाल कर रहे हैं । विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन के लिए चौकसी यूनिटों तथा जांच चौकियों की भी स्थापना की गई है । हरियाणा पशु– टीका संस्थाने, हिसार को, जो कि उत्तरी भारत का प्रमुख जैव उत्पादन केन्द्र है और आसपास के राज्यों को भी टीके सप्लाई करता है, पर्याप्त रूप से 'सुदृढ़ बना दिया 'जाएगा ताकि 197 8–7 9 में अतिरिक्त मात्रा में टीके बनाए जा सके । पशु–चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों की तथा रोग निदान के लिए आधुनिक उपकरणों, अर्थात् ऐक्स–रे–संयत्र आदि, की व्यवस्था करके तीन जिला पशु चिकित्सा अस्पतालों को भी अधुनातन बनाया जाएगा ।

डेरी विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में श्वेत क्रान्ति लाने के लिए सरकार डेरी विकास को प्राथमिकता दे रही है । चालू वित्त वर्ष के दौरान डेरी विकास निगम, हरियाणा को हिस्सा पूंजी के रूप में 40 लाख रुपये की राशि दी गई है । चालू वित्त वर्ष के दौरान उपबन्धित 50

लाख रुपये के मुकाबले में वर्ष 197 8– 79 में डेरी विकास के लिए 54 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

हरियाणा डेरी विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे भिवानी, अम्बाला 'और रोहतक कें दुग्ध संयत हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ को पट्टे पर दे दिए गए है । इसके परिणाम स्वरुप संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, कृषि

पुनर्वित्त विकास निगम तथा भारतीय डेरी निगम से ' व्याज की कम दैरों पर– कर्जे? ले सकता है । फरीदाबाद, सिरसा और हिसार के दुग्ध 'संयत्रो का निर्माण–कार्य– चल रहा हैं व्यौर यह वर्ष 197 8–? 9 के दौरान पूरा हो जाएगा । आगामी, वित्त वर्ष' केदौरान सिरसा तथा भूना के दुग्ध अवशीतन केन्द्र भी पूरे हो जाएँगे । 'वर्तमान दुग्ध संयतों को वित्तीय रूप से समर्थ बनाने के लिए उन्हें बहुविध बनाया जा रहा है ।

सहकारिता

हरियाणा की सहकारी संस्थाओं ने कृषि उत्पादन, स्वत रोजगार जुटाने, कृषि के लिये अपेक्षित सामान के वितरण, विपणन, कृषि–आधारित साधन, यूनिटों की स्थापना तथा समाज के कमजोर वर्गो की आर्थिक स्थिति को सुधारने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । हरियाणा ने वर्तमान कृषि उधार तथा सेवा सहकारी समितियों को फिर से चालू करने के मामले में अक्षम समितियों को मिलाकर देश के अन्य राज्यों का पथ प्रदर्शन किया है । 8, 565

ऐसी समितियो को मिला कर 2, 1 71 सक्षम यूनिट बना दिये गये हैं । ये पुनर्गठित समितियां प्रत्येक पटवार मुख्यालय में स्थापित की गई हैं, और ये कार्य–क्षेत्र में ग्रामीण लोगों की कृषि सम्बन्धी तथा कृष्येतर आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं ।

हरियाणा में सहकारी आन्दोलन हाल ही में तेज हुआ है और आशा की जाती है कि वर्ष 197 8– 79 के दौरान उधार समितियों की सदस्य संख्या 10 5 लाख से बढ़ कर 1, 2 लाख हो जाएगी । इस प्रकार 72. 61 प्रतिशत कृषि परिवारों को इस आन्दोलन के अन्तर्गत लाया जाएगा । सदस्यों की जमा राशि 1. 10 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1 50 करोड़ रुपये हो 'जाने और अल्पावधि तथा मध्यावधि कर्जे 75 करोड़ रुपये से बढ़ कर 80 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है ।

हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन. संघ (हैफेड) कृषि आधारित साधन यूनिट, जैसे दाल मिलें, धान के शैलर, मूंगफली के तेल की मिलें, एक कताई मिल, पशुचारा सवव और एक बेकरी यूनिट चला रही है । इसके अन्य कार्यों में कृषि उत्पादन का विपणन तथा कृषि के लिये अपेक्षित सामान अर्थात् रासायनिक खादों, नाशीकीटमारों, कीटनाशियों और पशुचारे की सप्लाई करना शामिल है । हैफेड. द्वारा स्थापित एक कताई मिल हाल ही में हांसी में चालू की गई है ।

इस समय रोहतक, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 4 सहकारी चीनी मिले कार्य कर रही हैं । सहकारी क्षेत्र में पांच और चीनी मिलें लगाने की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है । कीमतों को स्थिर करने और नियन्त्रित एवं अनिवार्य वस्तुओं 'को लोगों में वितरित करने –की व्यवस्था करंने के ' विचार से जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण नगरों में 17 सहकारी 'उपभोक्ता ' स्टोर खोले गये हैं । इन स्टोरों की हिस्सा पूंजी में वर्ष 1977–78 'के दौरान 3 लाख रपये 'की वृद्धि की गई है और वर्ष 197 8– 79 के दौरान इस प्रयोजन के लिये 4 लाख रुपये की और राशि दी जाएगी । अतीत में औद्योगिक सहकारी संस्थाए उचित दरों पर तथा उपयुक्त समय पर कच्चा माल न मिलने और विपणन सुविधाओं तथा तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव के कारण वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नही कर सकी हैं । सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लि दो अपेक्स संस्थाओं, अर्थात् हरियाणा राज्य सहका री औद्योगिक संघ । हरियाणा राज्य हथकरघा बुनकर अपेक्स सहकारी समिति को, जोकि सदस्य प्राथमिक सहकारी औद्योगिक समितियों के लिए इन सेवाओं की व्यवस्था करती है, सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है । औद्योगिक सहकारी संस्थाओं से सम्बन्धित स्कीमों के लिए वर्ष 1977– 78 में 18 33 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया था और वर्ष 197 8– 79 के लिए 12. 80 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैक को ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की खरीद, कुएं खोदने, नलकूप लगा ने तथा भूमि सुधार इत्यादि के लिये किसानों को दीर्घा वधि कर्जे देने के समूचे कार्य के लिए भारत के माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा विजयो– पहार प्रदान किया गया है । वन

वन विभाग वनों पर आधारित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ– साथ, राजस्थान के मरुस्थल को दक्षिणी एवं दक्षिण–पश्चिमी भाग में बढ़ने से रोकने और बार–बार पडने वाले सूखे तथा आने वाली बाढ़ों के नियंत्रण के कार्यों में भी लगा हुआ है । इस उद्देश्य से सड़कों, नहरों तथा रेलवे लाइनों के साथ वाले भू–भाग पर तथा सरकारी भूमि, मरुस्थल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सघन वनरोपण स्कीमें आरम्भ की गई हैं । चालू वर्ष के दौरान 8! 335 पंक्ति किलोमीटर और छ । 919 हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में वनरोपण किया जायेगा जिस पर कुल 1 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे । चालू वर्ष के दौरान 262 लाख रुपये के मु काबले में वर्ष 197 8– 79 के दौरान वन स्रोतों को बढाने । अनेक भू–संरक्षण निर्माण–कार्य करने तथा वन्य प्राणी विकास के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं गे । इन स्कीमों से वर्ष 197 8– 79 के दौरान 9, 700 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । बंजर पंचायती जमीनों पर पौधा–रोपण और फार्म वन संवर्धन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये

आयोजना तथा परियोजना निरूपण मशीनरी को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

सरकार बिचौलियों के अनाचा र को द्र करने तथा अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिये 197 8– 79 में विभागीय लकड़ी कटाई कार्यों को बढ़ाना चाहती है । चालू वित्त वर्ष की 113 लाख रुपये की प्रत्याशित आय के मुकाबले में अ गामी वर्ष में वनों से 130 लाख रुपये की आप हो ने की सम्भावना है ।

मछली पालन

राज्य की भूमि बंजर होने तथा जलवायु खराब होने के बावजूद यहां ऐसे पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध हैं, जिनको अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया और जहां मछली पालन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं । आगामी वित्त वर्ष में उच्च कोटि की मछलियों के पालन तथा मछली पालन के लिये तालाबों के सुधार के लिये राज्य योजना स्कीमों तथा केन्द्र चालित स्कीमों के अंतर्गत 48 85 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे । रोहतक तथा सोनीपत में दो मछली पालन विकास एजेंसियां स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन एजेंसियों के अन्तर्गत पंचायतों के तालाब मछली पालकों को 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिये जाएगे । इन एजेंसियों द्वारा 170 परिवारों को पूर्णकालिकय रोजगार तथा लगभग 1 700 व्यक्तियों को अंशकालिक रोजगार प्राप्त होगा । सरकार मछली पालन विकास निगम बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ।

उद्योग

राज्य सरकार ने ग्रामीण शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये रोजगार प्रधान ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिये एक नई स्कीम आरम्भ की है । इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न समुदायों से सम्बद्ध दो से चार ग्रामीण शिक्षित युवकों के समूह को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे यूनिट चालू करने के लिये रियायती वित्त, कच्चा माल, विपणन सहायता और तकनीकी जानकारी दी जाती है । प्रायरू इसमें समाज के कमजोर वर्गो के उद्यमकर्त्ता आएंगे । यूनिट चालू करने से पहले उन्हें इस विषय में प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस स्कीम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 110 औद्योगिक यूनिट स्थापित किए जाएंगे और आगामी वर्ष में ऐसे 330 और यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है । इससे चालु वर्ष में 1000 व्यक्तियों को और अगले वर्ष में 2, 500 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्राप्त होगा ।

इस वर्ष रबड़ और इंजीनियरी के सामान के लिये गुड़गांव में एक नया गुण– अंकण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है जिससे राज्य में ऐसे केन्द्रों की संख्या बढ़ कर 12 हो जायेगी । राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अन्तर्गत लघु उद्योग यूनिटों को 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी और 10 लाख रुपयें का व्याज रहित ऋण भी दिया जायेगा । इस वर्ष राज्य के पिछड़े घोषित क्षेत्रों में स्थापित 28 यूनिटों को नकद उपदान देने के लिये 20 लाख रुपये की राशि का उपबंध किया गया है ।

सड़कें

वर्तमान सरकार ने देहाती सड्कों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है, विशेषकर उन सड़कों की ओर जो गावों को सीमा–पार पंजाब और राजस्थान के गांवों से मिलाती है । हरियाणा के गांवों को पंजाब के गांवों से जोड़ने के लिए 24 सड़कों और हरियाणा के गांवों को राजस्थान के गांवों से जोड़ने के लिए 8 सड्कों के निर्माण –का प्रस्ताव है देहाडी लोगों की उपमण्डल मुख्यालयों तक –यात्रा. के लिए, जहां सडके नही हैं, –वहां उनके निर्माण के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. । चालू विल– वर्ष–कें अन्त– तक 640 किलोमीटर –लम्बी सडको का निर्माण किया जायेगा और 2 00 गावों को सड़क के नक्शे पर लाया जाएगा । लघु देहाती योजक सड्कों के निर्माण के. लिए भारत – सरकार से 30 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिससे 40 सड्कों का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिनकी कुल लम्बाई 53 किलोमीटर है । नई सड्कों के निर्माण के अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 150 किलोमीटर लम्बी सड्कों को चौडा किया जायेगा ।

भारी बाढ़ों के कारण सड्कों को बहुत नुकसान पहुंचा है और 12. 50 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है । जिन सड्कों 'को नुकसान पहुंचा है, उनकी मरम्मत के लिए भारत सरकार ने 3 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी है और निर्माण–कार्य चल रहे हैं । राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के

अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों– में क्तको के निर्माण के लिए विश्व बैक द्वारा 17. 73 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दिये जाने की सम्भाबना है । सरकार इस – राशि से अगले चार वर्षों में 1379 किलोमीटर लम्बी और सडके बना सकेगी । सड़कों की योजना के लिए उप– बन्ध चालू वित्त– वर्ष में 4 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है और वर्ष 197 8– 79 के लिए ै. 45 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

परिवहन

वर्ष 1977– 78 के दौरान हरियाणा परिवहन का, विशेषतरू ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार हुआ है । चालू वित्त वर्ष के अंत तक बसों की संख्या बढ़ कर 2, 178 हो जाने की सम्भावना है । वर्ष 1 97 8–7 9 के अंत तक बसों की संख्या में और 200 की वृद्धि होगी

राज्य परिवहन की बसों में प्रतिदिन 8 लाख यात्री याता करते हैं और ये लगभग 5 लाख किलोमीटर रास्ता तय करती हैं । हांसी का नया बस अड्डा मुकम्मल होने वाला है तथा सोनीपत, यमुनानगर और टोहाना में भी बस अंड्डो का निर्माण शुरु कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भिवानी जींद तथा कैथल में वर्कशाप भवनों का निर्माण–कार्य भी मुकम्मल हो चुका है । पहली अप्रैल, 1978 से सिरसा में नया डिपो खोला जायेगा ।

किफायत तथा कार्यकुशलता के हित में विभाग का प्रस्ताव है कि आगामी वर्ष में बस बॉडी निर्माण वर्कशाप स्थापित की जाये । विभाग चाहता है कि जनता की शिकायतों की ओर अधिक ध्यान दिया जायं तथा विभाग ने सारे डिपुओं में तथा राज्य मुख्यालय में शिकायत कक्ष खोले हैं ।

पर्यटन

वर्ष 197 7– 78 के दौरान, हरियाणा पर्यटन विभाग, राज्य मे पर्यटन विकास पर 85 लाख रुपये खर्च करेगा । जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सामान्य पर्यटकों के लिए सस्ते तथा साफ सुथरे आवास की व्यवस्था की जाये । विभिन्न पर्यटन केन्द्रो में यक्के शिविर कुटीर बना कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर टी गई है । इस वर्ष के दौरान, गुड़गांव जिला में तावडा के स्थान पर एक नया पर्यटन केन्द्र बनाया गया है । वर्ष 197 8– 79 के लिए पर्यटन विभाग का आयोजनागत परिव्यय 59.50 लाख रुपये नियत किया गया है । यह राशि वर्तमान पर्यटन केन्द्रों में अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने तथा गये पर्यटन केन्द्र बनाने पर खर्च की जायेगी । सूरज कुण्ड तथा बडखल पर्यटन केन्द्रों के मोटलो तथा शिविर कुटीरो मै पर्यटकों के लिये अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है ।

शिक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिये क्रमबद्ध तथा जी तोड प्रयत्न किए जा रहे हैए । वर्ष के दौरान नामदर्ज अभियान शुरू किये जाने के परिणामस्वरूप 65, 000 और बच्चे स्कूलों में दाखिल किये गये । वर्ष 1 97 8– 79 के दौरान 90000 और बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का प्रस्ताव है जिससे दाखिल बच्चों की संख्या बढ़ कर सम्पूर्ण भारत की 75 प्रतिशत औसत के मुकाबले में 81. 2 प्रतिशत हो जाएगी । बच्चों को अधिक संख्या में आकर्षित करने तथा स्कूलों में उनकी उप– स्यिति बनाये रखने के लिए 2, 859 प्राइमरी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 2. 48 लाख बच्चे आते हैं । वर्ष 197 8– 79 के दौरान! इसरू कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 4 लाख बच्चे आ जायेंगे ।

स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सभी वर्गों के अध्यापकों के लिए सेवावधि में प्रशिक्षण का वृहत् कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसे चालू भी रखा जा रहा है । चालू वर्ष के दौरान 69 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढाकर उन्हें मिडल स्कूल बनाने तथा 28 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है ।

सरकार, भारत सरकार की नीति के समरूप शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई 10+2 प्रणाली लागू कर रही है । शिक्षा की नई प्रणाली के अन्तर्गत कार्य अनुभव स्कूल पाठ्यक्रम का

अभिन्न अंग बन गया है और स्कूलों को कार्य अनुभव शिक्षण देने के योग्य बनाने के लिए कच्चा माल तथा उपस्करों आदि की खरीद के लिए चालू वित्त वर्ष में 2. 12 लाख रुपये के उपबन्ध के मुकाबले में वर्ष 1978–79 सें 7. 82 लाख लये खर्च करने का प्रस्त व हए । नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिये स्कूलों में प्रयोगशालाओं को उपस्कृत करने हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान 45. 39 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । नई शिक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक लागू करने योग्य बनाने लिए, के शैक्षिक. अधिकारियों तया अध्यापकों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करने के महत्व. को अनुभवें करते हुए सरकार ने प्रत्येक जिला में वयस्क शिक्षा केन्द्र खोले हैं । वर्ष 1 97 7– 78 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 260 लाख वयस्कों को लाना परिकल्पित है । यह संख्या वर्ष 1 97 8–7 9 के दौरान 3 लाख तक बढ़ जाएगी ।

कालिज में पढ़ने वाले. विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से परिचित करवाया जा रहा है और एन0एस0एस0 कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े वर्गो तथा, कम सुविधा प्राप्त लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । यह विचार है कि वर्ष 1 97 8– 79 के दौरान स्वयं सेवकों की वर्तमान संख्या दस हजार से बढ़कर बारह हजार हो जायेगी ।

खेलकूद

वित्त वर्ष 1978– 79 में सरकार विभिन्न खेलकूद कार्यकलापों के विकस पर 1. 02 करोड़ रुपये खर्च करेगी । इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था, स्टेडियमों का निर्माण, छात्रवृत्तियां देना, खेल प्रतियोगिताएं करवाना, ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों की स्थापना करना तथा राज्य में विभिन्न खेलकूद संस्थाओं को वित्तीय सहायता– अनुदान देना, शामिल है । राज्य में पहले ही 1 74 ग्रामीण खेलकूद केन्द्र स्थपित किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1 97 8– 79 में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने के लिए 8 0, 000 रुपये का उपबन्ध किया गया है । राज्य के कर्म चारियों के खेलकूद कार्यकलापों की देखभाल के लिये सिविल सेवा खेलन प्रतियोगिता नियंवण बोर्ड की स्थापना की जा रही है तथा वर्ष 1 97 8– 79 के दौरान इस कार्य के लिये एक लाख रुपये का उपवन्ध किया गया है ।

विशिष्ट खिलाड़ियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम चलाई गई है, जिसके लिए वर्ष 1 97 8– 79 के दौरान 2 58 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । इन छात्रावासों में चुने हुए खिलाड़ियों को भोजन तथा निवास की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी तथा जिस खेल में वे श्रेष्ठ हैं उन्हें उस खेल का गहन प्रशिक्षण. दिया जायेगा । राज्य खेलकूद परिषद् स्थापित करने पर भी सरकार विचार कर रही है ।

स्वास्थय

राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपचर्या में, विशेषत ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करने और उसे बहूविध बनाने के लिए सम्मिलित. प्रयत्न कर रही है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 12. 35 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के मुकाबले वे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 9 06 करोड रुपये खर्च किए जाने की सम्भावना है और वर्ष 1978–79 के लिए 2. 93 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

चालू वर्ष के दौरान दो औषधालय, एक हस्पताल और एक जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किये गये हैं । दो हस्पतालों में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था की गई है और 10000 की ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 50 और उप–केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं । एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और दो हस्पतालों के लिए नए भवन बनाने की भी स्वीकृति दी गई है ।

केन्द्रीय जनता सरकार के निर्देशों और उनकी स्वास्थ्य नीति के अनुसार 1978–7 9 की वार्षिक योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है । 2. 93 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से 43. 15 लाख रुपये की राशि उप–केन्द्र खोलने, उग्र–केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अतिरिक्त दवाइयों की व्यवस्था करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें परामर्श हस्पताल बनाने और

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने के लिए निर्धारित की गई है ।

अक्तूबर, 1977 से 25 चुने हुए ब्लॉकों में ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम शुरू की गई है । इस स्कीम को अम्बाला तथा महेन्द्रगढ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस स्कीम को लागू करने के लिए शेष नौ जिलों में से भी एक–एक ब्लॉक चुना गया है । इस स्कीम के अतर्गत समुदाय में से चुना गया एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक हजार जनसंख्या के लिए प्रारम्भिक चिकित्सा और स्वास्थ्य उपचर्या करेगा । इस कार्यकर्ता को 3 मास के प्रशिक्षण के दौरान 200 रुपये प्रतिमास वजीफा दिया जाएगा और उसके पश्चात् 50 रुपये प्रतिमास मानदेय दिया जाएगा । इस स्कीम के अन्तर्गत, दिसम्बर, 1977 के अन्त तक लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है । 197 8– 79 के अन्त तक, 2, 500 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 25 लाख जनसंख्या को पहले ही इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और क्रमानुसार समूचे राज्य को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा । इस स्कीम पर वर्ष 1977–78 के दौरान 8. 8. 5 लाख रुपये और वर्ष 197 8–? 9 के दौरान ३2 68 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है । देशीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए चालु वित्त वर्ष के दौरान एक नया आयुर्वेदिक निदेशालय स्थापित किया गया है ।

जन स्वास्थ्य तथा जल–सप्लाई

राज्य सरकार उन गांव–वासियों को पेय जल प्रदान करने की बड़ी इच्छुक है जिन्हें अपनी मूल आवश्यकता के लिये भी जल उपलब्ध नहीं होता । इस उद्देश्य के लिये चालू धिसे वर्ष में राज्य योजना के अन्तर्गत 2 00 करोड़ रुपये तथा केंन्द्र सरकार के त्वरित ग्राम जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1. 40 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में 22 स्कीमें हैं जिनमें 171 गांव आते हैं । आशा है कि इस वर्ष के दौरान 125 गांवों को जल सप्लाई सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी । समाकलित हरियाणा सिंचाई तथा सिंचाई–अधीन क्षेत्र विकास परि– योजना के लिये विश्व बैक से भी वित्तीय सहायता मांगी गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत 175 गांवों में जल–सप्लाई सुविधायें प्रदान करने के लिए 13. 20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे ।

वर्ष 19 78– 79 में, राज्य के सामान्य कार्यक्मों के अन्तर्गत ग्रामीण जल– सप्लाई के लिये 1. 00 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और विश्व बैक की स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले गांवों के लिये 3 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगे । आशा है कि केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन राशि प्राप्त होने पर तथा उनके त्वरित ग्राम जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन आगामी वर्ष मेँ 125 और गांवों को जल सप्लाई सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी ।

शहरी क्षेत्र में, वर्तमान सेवाओं को बडाने के अतिरिक्त एक और नगर में आंशिक रूप से जल सप्लाई सुविधायें प्रदान 'करने तथा टो और नगरों में बहुंत कम मल–व्यवस्था के लिए वर्ष 1978–79 के दौरान 1 50 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है 1 चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लियें 1 43 करोड रुपये का उपबन्ध है और इस वर्ष एक नगर में आंशिक रूप से जल–सप्लाई प्रदान करने तथा दों और नगरों में बहुत कम मल–व्यवस्था प्रदाम करने की सम्भावना है ।

आवास

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है, हरियाणा में जनसंख्या, की वृद्धि– दर अधिक होने तथा तीव्र औद्योगीक रहा के कारण ग्रामीण जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में चले जाने से आवास समस्या गम्भीर बन गई है । मकानों की बढ रही मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा आवास बोर्ड ने मार्च, 1977 के अन्त तक 3, 500 मकान मुकम्मल कर लिए थे । बोर्ड चालू वित्त वर्ष के अन्त तक लगभग 1, 700 और मकान मुकम्मल कर लेगा और उसका आगामी वर्ष के दौरान 4, 500 मकान और बनाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है ।

आगामी वित्त वर्ष में निम्न आय वर्ग आवास स्कीम तथा मध्यम आय वर्ग आवास स्कीम के अन्तर्गत क्रमश 10 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है । ग्रामीण

क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को मुफ्त आवास–स्थल देनेकी स्कीम के अतर्गत चालू वर्ष में 7, 000 प्लाट देने के लिए 10 लाख रुपये तथा आगामी वर्ष में लगभग 1, 500 आवास स्थल देने के लिह 2 लाख रुपये कां उपबन्ध किया गया है ।

आगामी वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी मकान देने के लिए 61. 00 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे । सरकारी कर्मचारियो को अपने मकान बनाने के लिंए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कंचे देने हेतु 83 लाख रुपये का क्य– बन्ध किया गया है । शहरी क्षेत्रो में रहने वाले आर्थिक तौर पर पिछड़े उन व्यक्तियो को, जिनके अपने मकान स्थल या निर्मित मकान नहीं हैं, सहायता देने के लिए यह निर्णय लिया है कि श्रेणी । तथा ।। नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5, 000 रुपये तक की लागत का निर्मित मकान दिया जाए । अलाटियों से इन मकानों की लागत 30 वार्षिक किश्तों में वसूल की जाएगी 1 अधिसूचित क्षेत्र समितियों में आने वाले शहरी क्षेत्रों के बेघर व्यक्तियों को 50– 50 वर्ग गज के प्लॉट देने का प्रस्ताव है । प्लॉट की लागत 5 बराबर किश्तों में वसूल की जाएगी ।

रोजगार

राज्य की व्यवस्थित अर्थ–व्यवस्था के क्षेत्र में रोजगार में 4 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 2. 8 प्रतिशत हुई है । रोजगार कार्यालयों में दर्ज 2. 30

लाख व्यक्तियों में से वर्ष 1977 के दौरान 3 7, 791 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है । इस संख्या में अनुसूचित के 6, 638 व्यक्ति तथा 2, .18 2 भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित है । विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के भरसक प्रयत्न किये गये तथा उनमें से 457 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया । यह महसूस करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी देनों सम्भव नही है, विभाग ने इन्हें स्वतः रोजगार करने में सहायता देने का काय' आरम्भ किया है । विभाग द्वारा दी गई सहायता तया मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 1, 762 व्यक्तियों ने स्वयं रोजगार आरम्भ किया । उनमें से 1, 750 व्यक्तियों को विभिन्न बैकों तथा वित्तीय संस्थाओं से 34. क् 9 लाख रुपये के ऋण प्राप्त करने में सहायता दी गई । वर्ष 197 8— 79 के लिये 8. 00 लाख रुपये के खर्च का उपबन्ध है । चालू वित्त वर्ष में चण्डीगढ में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय तथा राज्य में 1 ग्रामीण रोजगार कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्रम कल्याण

मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि देश में आपात स्थिति हटाने के परिणाम— स्वरूप फैक्टरियों में कामगारों ने अपने प्रबन्धकों से अपनी माँगों को मनवाने के लिए हड़तालें तथा प्रदर्शन करने आरम्भ कर दिये और राज्य सरकार के सक्रिय तथा सौहार्दपूर्ण बर्ताव से प्राय सभी मामलों में कामगारों तथा प्रबन्धकों के बीच विवादों तथा मन्त्रीोदों का निपटान शांतिपूर्ण ढंग से हो

गया है । पंजीकृत फैक्टरियों की संख्या वर्ष 1976 में 2, 382 से बढ़कर वर्ष 1977 के दौरान 2, 51 1 हो गई । सर्टीफाइंग सर्जन को आधूनिक चलती–फिरती गाड़ी दी गयी है जिसमें लघुरूप में ऐक्सरे उपकरण तथा प्रयोगशाला फिट हैं । महिला कामगारों के लाभ के लिये अधिनियमित विभिन्न कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक महिला कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी । वर्ष 197 8–7 9 के दौरान यमुनानगर, जगाधरी, पानीपत, अम्बाला,रोहतक बहादुरगढ़, भिवानी तथा हिसार के स्थानों पर बालगृह खोले जाएंगें जिन पर 40, 000 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों के उत्थान को प्राथमिकता दी जा रही हए । उनके आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नयन के लिए विभिन्न स्कीमें लागू की जा रही हैं जिनमें छात्रवृत्तियां देना, शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, कृषि भूमि की खरीद के लिए कर्जे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/स्कूलों में प्रशिक्षण के लिए वजीफे । मकानों, पेय–जल कुओं तथा चौपालों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता शामिल है ।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम राज्य सरकार द्वारा किये गये उपबन्ध को अनु. पूरित करता रहा है और उसने 3 1–

1 2– 77 तक ब्याज की रियायती दरों पर 1 25 करोड़ रुपये के कर्जे स्वीकृत किये जिनमें से 88. 84 लाख रुपये की राशि 2, 383 हरिजनों को विभिन्न कारोबार तथा व्यवसाय करने के लिए दी गई है ।

समाज कल्याण सेवाएं

समाज कल्याण विभाग द्वारा निराश्रित महिलाओं तथा उन पर आश्रित बच्चों, वृद्ध तथा निर्बल, विकलांग तथा अपचारी व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्कीमें बनाई गई हैं तथा उन पर अमल किया गया है । वर्ष 197 8– 79 के दौरान इन व्यक्तियों के लिए बनाई गई स्कीमों पर 125. 14 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । 14 लाख रुपये की राशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 'पोषाहार' के लिए निर्धारित की गई है । स्वैच्छिक सस्थाओं द्वारा करनाल तथा भिवानी में चलाये जा रहे अनाथालयों में 102 अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल की जा रही है । निराश्रित बच्चों की देखभाल करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रत्येक निराश्रित बच्चे के लिए 30 रुपये प्रतिमास की दर से अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है ।

शहरी गन्दी बस्तियों में रह रहे बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 1 3 कस्बों में विशे पोषाहार कार्यक्रम शुरु किये गए हैं । इस स्कीम के अन्तर्गत 1 6, 550 बच्चे, गर्भवती तथा शिशुओं की माताएं लाभ उठा रही है ।

वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 6, 510 निराश्रित पुरुषों तथा महिलाओं को 50 रुपये प्रतिमास रेशन दी जा रही है । वित्त वर्ष 197 8– 79 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 8 000 पेंशनभोगी लाने के लिए 42. 31 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी ।

कर वसूली तथा नशाबन्दी

जुलाई–अगस्त, 1977 में के अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण राज्य की अर्थ–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप रोहतक, गुड़गांव तथा महेन्द्रगढ़ के जिलों में कर की वसूली कमहुई । किन्तु फिर भी, वर्ष 197 6– 77 में हुई 106. 06 करोड रुपए की वसूली के मुकाबले में वर्ष 197 7–78 के दौरान विभाग की राजस्व वसूली 120. 40 करोड़ रुपए की होगी । वर्ष 197 8– 79 में 135.43 करोड़ रुपए की कुल वसूली होगी ।

सरकार को बिक्री कर तथा अन्य करों की पद्धति बदलने तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने की समस्या की पूरी जानकारी है । बिक्री कर तथा अन्य करों की उगाही को सरल और युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए बिक्री–कर सलाहकार समिति बनाई गई है ।

राज्य सरकार नशाबन्दी लागू करने के प्रयत्न कर रही है । देशी शराब अथवा भारत में बनी विदेशी शराब के लिए कोई नए लाईसैंस नहीं दिए जाएंगे । आगामी वर्ष में नशाबन्दी के

दिनों की संख्या 15 से बढ़ाकर 79 कर दी जाएगी । सिरसा जिले में गांव चौटाला के 8 मील के घेरे तथा जुडगांव जिले के तावडू? के आस पास तथा महेन्द्रगढ़ जिले में 143 गांव को पहले ही मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है । सरकार नशाबन्दी लागू करने तथा कराधान नीति के लिए मार्ग निर्देश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर विचार कर रही है ।

नशाबन्दी की नीति को लागू करने के फलस्वरूप हरियाणा सरकार को राजस्व में होने वाली हानि की पूर्ति्त के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा ।

सरकारी कर्मचारी

इस बारे में दो राय नहीं है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी अनुशासनबद्ध, निष्ठावान तथा समर्पण की भावना से कार्य करने वाले हैं । यह विशेष रूप से प्रसन्नदायक है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिन्हे कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से निष्ठावान हैं, तथा समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं । अभी तक जारी मुद्रा स्फीति के दृष्टिगत, अपने कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक होने के कारण, सरकार ने उन्हें पहली जनवरी, 1978 से मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किश्त देने का निर्णय किया है । इससे सरकार के खजाने पर लगभग 1. 75 करोड़ रुपए का अति– रिक्त भार पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, सरकार ने

सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए दो महत्व– पूर्ण निर्णय लिए हैं । पहला, यह निर्णय किया गया है कि सेवा–निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मृत्यु एवं सेवा–निवृत्त उपदान में से परिवार पैशन स्कीम, 1984 की ओर उनके अंशदान के रूप में दो मास के वेतन के बराबर की कटौती को बन्द कर दिया जाय । दूसरे, यह निर्णय किया गया कि सेवा–निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को उसके खाते में, 180 दिन की अधिकतम सीमा तक, बाकी बचे अर्जित अवकाश के बदले में नकद भुगतान कर दिया जाए । इसके अतिरिक्त सरकार अपने सेवा–निवृत्त कर्मचारियों के कल्याण का निरन्तर ध्यान रख रही है । पहली जनवरी, 1973 से पूर्व–सेवा–निवृत्त होने वाले हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 5 से 35 रुपए प्रतिमास की तदर्थ राहत देने? का निर्णय किय?? गया है ताकि उन्हें इस मामले में पंजाब सरकार के पैशनरों के बराबर लाया जा सके । इसके अतिरिक्त पहली जनवरी, 1978 से बैंकों के माध्यम से पैशनों का भुगतान करने की– प्रणाली आरम्भ कर दी गई है । आरम्भ में यह सुविधा केवल । तथा ।। श्रेणी से सेव निवृत पैशनरों को ही दी जाएगी । इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद इसे अन्य वर्गों के पैशनरों पर भी लाग जरूर दिया जाएगा । ये कल्याण के ठोस पग हैं और हमें आशा है कि हमारे कर्मचारी हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए उत्साह तथा निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे, क्योंकि अन्तत जनता के कल्याण पर ही उनका अपना कल्याण निर्भर करता है ।

बजट के घाटे को पूरा करने के लिए उपाय

राज्य के बजट में वर्ष 197 8– 79 के अन्त में 26 89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है । राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1978 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक और किश्त दिए जाने का निर्णय के परिणामस्वरूप यह घाटा 1 75 करोड़ रुपए और बढ जाएगा । बजट अनुमान 197 8– 79 में सम्मिलित राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अनुमान अभी अनन्तिम हैं । राज्य की वार्षिक आयोजना 1978–79 के लिए सामान्य स्तर पर केन्द्रीय सहायता कल्पित की गई है । हमें पूर्ण आशा है कि भारत सरकार के साथ बिचार–विमर्श के परिणामस्वरूप इसमें पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ नियन्त्रण उपायों, जिनसे न केवल हमारे राज्य को अपितु राजस्थान राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी लाभ पहुंचेगा, पर प्रस्तावित अतिरिक्त खर्च करने की तात्कालिक आवश्यकता को योजना आयोग ने पहले ही अनुभव किया है । इसके बाद भी पर्याप्त घाटा शेष रह जाएगा, जिसे अंशत विकासेतर व्यय में किफायत करके, करों तथा सरकार को देय बकायों की प्रभावी वसूली द्वारा तथा अतिरिक्त साधन जुटा कर पूरा करने का प्रस्ताव है ।

अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किर! जा रहे हैं:–

(1) यह प्रस्ताव है कि सड़क कर सार्वजनिक वाहनों पर 1, 250 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 1, 500 रुपए वार्षिक प्रति वाहन, संविदा वाहन बसों पर 130 रुपए प्रति सीट वार्षिक से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति सीट वार्षिक तथा टैक्सियों पर 75 रुपए प्रति सीट से बढ़ाकर 10 छ रुपए प्रति सीट वार्षिक कर दिया जाए । यह भी प्रस्ताव है कि मोटर साइकलों, स्कूटरों, कारों तथा जीपों पर सड़क कर की वर्तमान दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ।

परिणाम स्वरुप सड़क कर से आय में 28 लाख रुपए प्रति वर्ष की वृद्धि होगी ।

(2) यान्नी कर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिससे वर्ष 197 8– 79 के दौरान 1. 80 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है । यानी कर की दर धु–ससे पहले अप्रैल, 1973 में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई थी ।

(3) मद्यपान को निरुत्साहित करने के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि शराब को और मंहगी करने के लिए (क) विदेशी शराब तथा भारत में बनी विदेशी शराब पर बिक्री कर 10 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए तथा (ख) देशी शराब पर 'स्टिल हैड डयूटी' 8. 00 रुपए प्रति प्रूफ लिटर से बढ़ाकर 9 00 रुपए प्रति प्रुफ लिटर कर दिया जाए । इन उपायों से लगभग 1 70 करोड़ रुपए वार्षिक की अतिरिक्त आय होने का अनुमान हैं ।

(4) वादा तथा ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन गठित आयोग अथवा पंजाबी खादी तया आम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों के जिन वर्गों के हक में प्रामाणिकका प्रमाण–पल जारी किया गया था, उन सभी को हरियाणा सा–मान्य निकी कर अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अधीन छूट दी गई थी । कुटीर उद्योग के विकास के हित में यह रियायत दी गई थी । परन्तु यह पाया गया है कि कई बार अच्छे समृद्ध व्यक्तियों ने भी अपने हक में जारी करवाए प्रामाणिकता प्रमाण–पत्र के आधार पर बिक्री कर से बचने के निए फर्जी सहकारी समितियां बनाकर इस सुविधा का दुरुपयोग किया है । सरकार कुटीर तथा ग्राम उद्योग कोई वृद्धि को बढावा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है, परन्तु वह इस बात के लिए भी उतनी ही उत्सुक है कि जो समितिया वास्तव में प्रमाणित नही हैं, उनके द्वारा उपर्युक्त रियायत के दुरुपयोग को रोका जाए । अतः जिन मामलों में कारोबार की वार्षिक बिक्री 7 5, 000 रुपए से बढ़ जाती है, उनमें बिकी कर से छूट की रियायत वापिस लेने का. निर्णय लिया गया है । इस निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लगभग 24 लाख रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय होने की सम्भावना है ।

(5) सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च गत वर्षो में निरन्तर बढ्ता रहा है । इससे, अन्य बातों के साथ–साथ साधारण खर्च में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है और सब आबियाना, स्वामी

उपशुल्क तथा अन्य प्राप्तियों से होने वाली कुल आय से भी अधिक निवेश वाली इन परियोजनाओं का ब्याज प्रभार तथा कार्य खर्च भी पूरा नहीं होता । अन्य सरकार ने राज्य की सिंचाई प्रणाली के संधारण खर्च तथा उससे होने वाली आय के अन्तर को पूरा करने के प्रयास में वर्ष 1975– 78 में समुन्नति कर को समाप्त करके आबियाना बढ़ा दिया था । किन्तु सिंचाई परियोजनाओं के चरणों में पूरा हो जाने तथा उनके विकास के साथ–साथ संधारण खर्च में निरन्तर वृद्धि होते रहने के कारण यह अन्तर पूरा नहीं हो सका । राज्य की अर्थ–व्यवस्था के त्वरित विकास कें लिए साधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत यह उपयुक्त ही है कि सिंचाई– सेवाएं कम से कम अपना संधारण खर्च स्वयं पूरा करे । यह की गई सेवाओं के लिए प्रभार है और इन सेवाओं के लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को राज्य के विकास– कार्यों में, जोकि मुख्यतरू कृषि–उत्पादन बढ़ाने तथा सिंचाई और बिजली सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेत है. उपयुक्त योगदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए । अब. यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान आबियाने में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए । इससे राज्य को लगभग एक करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

(6) राज्य सरकार ने 1– 9– 1977 से बिकी' कर पर अधिप्रभार कीं दर 2 प्रतिज्ञात से बनकर 1 5 प्रतिशत कर दी थी । अनुमान था कि अधिप्रभार दूर में इस वृद्धि से 197 8– 79 के दौरान राज्य सरकार को 2.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय

होगी । उपभोक्ताओं को राहत दे ने के विचार से इस मामले पर पुनर्विचार हया गया और सरकर ने अधिप्रभार दर 1 5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के परिणाम– स्वरूप राज्य सरकर की आय में लगभग 1 50 लाख रुपए की कभी हो जाएगी ।

इन उपायों का अन्तिम परिणाम यह होगा कि आगामी वर्ष के दौरान राज्य के साधनों मैं 3 47 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और बजट के अनुमानित घाट में तदनु रूह कमी हो जाएगी ।

राज्य की विकास–आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्ताव अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं । हमने वर्ष 197 8– 79 के दौरान वार्षिक आयोजना स्कीमों पर 210 करोड रुपए खर्च करने है और ये स्कीमें राज्य में उत्पादन और समृद्धि बढ़ाने तथा वर्षानुवर्ष आने वाली बाढ़ों के परिणामस्वरुप हो ने वाली हानि से जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई हे । मुझे विश्वास है कि हरियाणा को प्रगति तथा समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के प्रयास में सरकार को माननीय सदस्यों कथा राज्य की जनता से पूर्ण सहयोग गिरेगा ।

आभार प्रदर्शन

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं वर्ष 197 8– 79 के बजट अनुमान तैयार क्रने में वित्त विभाग के अधिकारियों तथा

कर्मचारियों द्वारा किए गए कठोर परिश्रम के लिए उनकी सराहना करता हुआ उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं । मैं महालेखापाल, हरियाणा से प्राप्त अन्त्य सहायता के लिए उनका आभारी हू । बजट के मुद्रण में चण्डीगढ प्रशासन तथा राजकीय प्रैस, हरियाणा से प्राप्त सहयोग के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं । माननीय महोदय, अब मैं वर्ष 1 97 8– 79 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं । जय हिन्द।

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह इसलिए किया जा रहा है कि किसान आन्दोलन नहीं कर सकते?

Mr. Speaker : This is not the proper opportunity. आपको 4 दिन का टाईम मिलेगा.....

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब,

Mr. Speaker : No, Rao Sahib, I am on my legs. Please sit down.

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे इजाजत लेकर यह पूछना चाहता हूं कि किसान आन्दोलन नहीं कर सकता

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल) : आन्दोलन वाले तो यह हमारी तरफ बैठे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : किसानों के नेता का राज है? – (विध्न) यह कभी किसानों से पूरी की जा रही है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : अब आपके बहकावे में व्यापारी नहीं आएंगे । (विध्न)निकल गए हाथ से । (विध्न)

चौधरी देवी लाल : दोन ओं ही आपके बहकावे में आ जाएंगे? (विध्न)आन्दोलन करो तो (विध्न) ।

Mr. Speaker : The House stands* adjourned till 2 P.M. on Monday, the 6th March, 1978.

12.02 बजे

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 6th March, 1978).